नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 060
दि. 02.12.2025,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

श्रीलंका में चक्रवात 'दित्वा' ने मचाई तबाही: 334 मृतक, दस लाख से अधिक लोग विस्थापित, राहत अभियान युद्धस्तर पर जारी

(जीएनएस)। कोलंबो। श्रीलंका इस समय इतिहास के सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं में से एक चक्रवाती तूफान 'दित्वा' के तांडव का सामना कर रहा है। भारी बारिश, तेज हवाओं और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन ने द्वीप के बड़े हिस्से को तहस-नहस कर दिया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 334 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग लापता हैं और लगभग दस लाख से अधिक लोग अपने घरों से बेघर होकर राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। सबसे अधिक तबाही कैंडी, बादुल्ला, नुवारा एलिया और कुरुनेगला जिलों में दर्ज की गई है। कैंडी में 88 मौतें हुई हैं और 150 लोग लापता बताए जा रहे हैं। राहत और पुनर्वास कार्य युद्धस्तर पर जारी है। देशभर में 1,494 राहत शिविरों को सक्रिय किया गया है, जहां लगभग दो लाख लोग अस्थायी रूप से रह रहे हैं। इन शिविरों में भोजन, पानी और प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही है। गम्पाहा, बादुल्ला और कोलंबो ज़िले सबसे अधिक विस्थापितों का बोझ झेल रहे हैं। इस दौरान पुट्टलम में बचाव अभियान के दौरान श्रीलंका एयर फ़ोर्स का बेल-212 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पांच लोग घायल हुए। वहीं मालिसिरिपुरा (कुरुनेगला) में भूस्खलन के मलबे में करीब 200 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है।

प्रभावित क्षेत्रों में सेना, वायुसेना और स्थानीय प्रशासन लगातार रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। कोलंबो से कई विशेष टीमें प्रभावित क्षेत्रों में भेजी गई हैं। कई जलाशयों की क्षमता अधिक होने के कारण उनके गेट खोलने से निचले इलाकों में पानी और बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ और खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि चक्रवात अभी भी देश के उत्तर की ओर सक्रिय है और कई जिलों में तेज बारिश और हवाओं की संभावना है।

अंतरराष्ट्रीय सहायता की अपील के बाद भारत ने 'ऑपरेशन सागर बंधु' के तहत बड़े पैमाने पर बचाव और राहत कार्य शुरू किया। कोलंबो एयरपोर्ट पर फंसे भारतीय नागरिकों के अंतिम जत्थे को वायुसेना के विमान के माध्यम से तिरुवनंतपुरम पहुंचाया गया। एयरलिफ्ट के दौरान भारतीय यात्रियों ने 'भारत माता की जय' का नारा लगाकर भारतीय वायुसेना का आभार व्यक्त किया। अब तक 300 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया जा चुका है। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने भूस्खलन और बाढ़ से कटे कोटमाले इलाके से 45 लोगों को बचाया, जिनमें छह गंभीर रूप से घायल और चार बच्चे शामिल थे। राहत कार्य को मजबूती देने के लिए 57 श्रीलंकाई सैनिकों को भी प्रभावित क्षेत्रों तक पहुँचाया गया।

भारत ने मानवीय सहायता के रूप में 21 टन राहत सामग्री भेजी, जिसमें खाने-पीने की वस्तुएँ, दवाइयाँ और आपातकालीन उपकरण शामिल हैं। इसके अलावा नौसेना का आईएनएस सुकन्या त्रिंकोमाली पहुंचकर राहत सामग्री वितरित कर चुका है, जबकि 80 से अधिक एनडीआरएफ कर्मी प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य में जुटे हैं।

श्रीलंका सरकार ने इसे हाल के वर्षों की सबसे भयावह प्राकृतिक आपदाओं में से एक करार दिया है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से सहायता की मांग की है। अब राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है, और प्रभावित लोगों के पुनर्वास और घर लौटने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। इस भयानक तूफान ने श्रीलंका के लाखों लोगों की जिंदगी को तहस-नहस कर दिया है, और अब उनकी सुरक्षा, राहत और पुनर्वास ही सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई है।

शेख हसीना, उनकी बहन और ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप सिद्दीकी को सजा, पूर्व पीएम पर एक और कानूनी वार

(जीएनएस)। ढाका। बांग्लादेश की राजनीति रविवार को उस समय हिल गई जब ढाका की एक विशेष अदालत ने बहुचर्चित राजुक पूर्वांचल न्यू टाउन परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोपों पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। लंबे समय से विवादों और जांचों में घिरे इस मामले में अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनकी बहन शेख रेहाना और ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप सिद्दीकी को सजा देकर साफ संकेत दे दिया कि न्यायिक कार्रवाई अब किसी राजनीतिक हैसियत की मोहताज नहीं है। अदालत के आदेश के अनुसार शेख हसीना को पाँच वर्ष, शेख रेहाना को सात वर्ष, जबकि ट्यूलिप को दो वर्ष कारावास की सजा हुई। ट्यूलिप और रेहाना पर एक-एक लाख टका का जुर्माना भी लगाया गया है और कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जुर्माना न चुकाने की स्थिति में ट्यूलिप को छह माह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे। विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रबीउल आलम ने इस फैसले को बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूर्वाह्न 11 बजे सुनाया। फैसले के वक्त अदालत परिसर में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती रही, क्योंकि बांग्लादेश में इस मामले को लेकर पिछले कई महीनों से राजनीतिक तनाव लगातार बना हुआ था। उल्लेखनीय है कि तीनों प्रमुख आरोपित अदालत में मौजूद नहीं थे। ढाका ट्रिब्यून के अनुसार 78 वर्षीय शेख हसीना पिछले तख्तापलट के बाद से भारत में रह रही हैं और वहां से ही अपनी कानूनी लड़ाइयों पर नज़र रख रही थीं। इस बीच उनकी अनुपस्थिति में फैसला जारी होने से विपक्ष और समर्थकों दोनों में नई बहस शुरू हो गई है।

मामला सिर्फ तीन लोगों तक सीमित नहीं रहा। इस घोटाले में कुल 14 और आरोपितों को पाँच-पाँच वर्ष की सजा सुनाई गई, जिनमें पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नौकरशाह और कई पूर्व सरकारी अधिकारी शामिल हैं। भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (एसीसी) ने यह मामला इसी वर्ष 13 जनवरी को दर्ज किया था और उसके बाद से लगातार दस्तावेज़ी सबूत, फाइलों और भूमि आवंटन से जुड़ी विस्तृत जांच की जा रही थी। अदालत ने सभी आरोपों को गंभीर माना और साफ कहा कि सरकारी संपत्ति और भूमि उपयोग में की गई अनियमितताओं ने राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुँचाया है।

दोषी ठहराए गए अन्य लोगों में शरीफ अहमद, काजा वाशी उद्दीन, मोहम्मद ओलीउल्लाह, सैफुल इस्लाम सरकार, पूरबी गोल्डर, अनीसुर रहमान मिया, मोहम्मद खुर्शीद आलम, तन्मय दास, मोहम्मद नासिर उद्दीन, शमसुद्दीन अहमद चौधरी, नूरुल इस्लाम, नायब अली शरीफ, मजहरुल इस्लाम और मोहम्मद सलाहुद्दीन के नाम शामिल हैं। ये सभी परियोजना की स्वीकृति, भूमि आवंटन और मूल्यांकन प्रक्रियाओं से जुड़े पदों पर थे तथा परियोजना से संबंधित कथित घोटाले में अहम भूमिका निभाने के आरोप में लंबे समय से जांच के दायरे में थे।

यह भी उल्लेखनीय है कि यह फैसला शेख हसीना के खिलाफ पहली बड़ी कार्रवाई नहीं है। इससे पहले एक अन्य वित्तीय अनियमितता मामले में उन्हें 21 वर्ष की सजा सुनाई जा चुकी है। इतना ही नहीं, इसी नवंबर में बांग्लादेश अपराध न्यायाधिकरण–1 ने छात्र विद्रोह के दौरान कथित मानवता-विरोधी अपराधों के लिए उन्हें मृत्युदंड भी सुना दिया था।

वक्फ संपत्तियों के डिजिटल रजिस्ट्रेशन पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, समय सीमा बढ़ाने से किया इनकार; ट्रिब्यूनल से राहत लेने को कहा

(जीएनएस)। नई दिल्ली। वक्फ संपत्तियों के डिजिटाइजेशन और रजिस्ट्रेशन को लेकर पूरे देश में जारी हलचल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि छह दिसंबर को समाप्त हो रही समय सीमा को बढ़ाया नहीं जाएगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यदि तकनीकी दिक्कतों या व्यावहारिक समस्याओं के कारण 'उम्मीद' पोर्टल पर समय से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए अदालत नहीं, बल्कि वक्फ ट्रिब्यूनल सही मंच है। कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत ट्रिब्यूनल के पास समय सीमा बढ़ाने का अधिकार उपलब्ध है और आवेदकों को वही विकल्प अपनाना चाहिए।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने बताया कि छह महीने की तय अवधि में आधा से अधिक समय तो वक्फ कानून में संशोधन पर आए अंतरिम आदेशों की वजह से ही निकल गया। पोर्टल लगातार तकनीकी समस्या देता रहा और सर्वर धीमा रहने से फॉर्म भरना बेहद मुश्किल हो गया। उनका कहना था कि 100 साल से अधिक पुराने वक्फों की पूरी जानकारी जुटाना आसान नहीं है और पोर्टल बिना सभी सूचनाओं के आवेदन स्वीकार नहीं करता। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि संशोधन 8 अप्रैल को लागू हुआ, पोर्टल 6 जून से चालू हुआ और नियम 3 जुलाई को आए—इस बीच उपलब्ध समय बेहद कम था।

केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि बड़ी संख्या में संपत्तियां पहले ही रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। लेकिन अधिवक्ता एम.आर. शमशाद ने कहा कि समस्या नए रजिस्ट्रेशन की नहीं बल्कि पुराने रजिस्ट्रेशन के डिजिटाइजेशन की है, और इस हिस्से को अंतरिम आदेश में ठीक से संबोधित नहीं किया गया।

पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साफ कहा कि कोर्ट समय सीमा बढ़ाने के आग्रह पर विचार नहीं करेगा। वक्फ अधिनियम की धारा 3बी ट्रिब्यूनल को समय सीमा बढ़ाने का अधिकार देती है, इसलिए सभी आवेदक अंतिम तिथि से पहले ट्रिब्यूनल से संपर्क करें और वहीं राहत की मांग करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि तकनीकी दिक्कतें होने के बावजूद कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना सभी पक्षों की जिम्मेदारी है।

एपस्टीन फाइल्स का साया भारत पर: पृथ्वीराज चव्हाण के बयान से राजनीतिक तूफ़ान, क्या सत्ता बदलने वाली है?

(जीएनएस)। मुम्बई की राजनीति उस दोपहर जैसे दहक उठी, जब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कराड में अपने आवास पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ऐसा दावा कर दिया, जिसने दिल्ली तक की हवा भारी कर दी। शांत और संतुलित छवि वाले चव्हाण ने जब मीडिया के सामने कहा कि "एक महीने के भीतर देश में सत्ता परिवर्तन हो सकता है और प्रधानमंत्री पद पर एक मराठी नेता बैठ सकता है," तो यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं रहा, बल्कि सियासी हलकों में तूफ़ान बनकर फैल गया।

कराड की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल बेहद साधारण-सा था—चव्हाण के बगल में अजीतराव पाटिल-चिखलीकर, तालुका कांग्रेस अध्यक्ष नामदेव पाटिल और शहर अध्यक्ष एडवोकेट अमित जाधव बैठे थे। लेकिन जैसे ही चव्हाण ने एपस्टीन फाइल्स का जिक्र किया, वातावरण अचानक भारी हो गया। उनके चेहरे पर सामान्य गंभीरता थी, पर शब्दों में इतना वजन कि पूरा मीडिया जगत चौकन्ना हो गया।

चव्हाण ने दावा किया कि अमेरिका के उद्योगपति जेफ्री एपस्टीन के अवैध साम्राज्य से जुड़ी करीब 10,000 पन्नों की गोपनीय फाइल अमेरिकी संसद में सुरक्षित रखी हुई

है। यह वही फाइल है, जिसे सार्वजनिक करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अंतरराष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ रहा है। चव्हाण के अनुसार, इस फाइल में दुनिया भर की कई शक्तिशाली हस्तियों के नाम शामिल हो सकते हैं—और इसी संभावना में भारत की राजनीति को हिलाने की ताकत छुपी है।

उन्होंने कहा कि यदि इस सूची में किसी भारतीय अत्यंत वरिष्ठ राजनेता का नाम आता है, तो देश में राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल सकता है। चव्हाण ने तो यह तक कह दिया कि भारत को अगले एक महीने में नया प्रधानमंत्री देखने को मिल सकता है—वह भी एक मराठी नेता। यह दावा इतना विस्फोटक था कि उसके बाद मौजूद हर नेता और पत्रकार जैसे उसी वाक्य में अटक गया। चव्हाण यहीं नहीं रुके। उन्होंने बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के उस वीडियो का भी उल्लेख किया, जिसमें स्वामी ने संकेत दिया था कि यह फाइल जल्द ही उनके पास उपलब्ध होगी और इसमें कई "चौंकाने वाले खुलासे" शामिल हैं। जब एक वरिष्ठ बीजेपी नेता भी ऐसी ही आशंका जता रहा हो, तो चव्हाण के दावे को राजनीतिक हल्कों ने हल्के में नहीं लिया।

उनका कहना था कि यह मामला सिर्फ किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा का नहीं, बल्कि देश की अंतरराष्ट्रीय छवि और वैश्विक राजनीतिक समीकरणों से भी जुड़ा है। यदि फाइल सार्वजनिक होती है और उसमें भारत से संबंधित कोई नाम आता है, तो इसका असर केवल दिल्ली की सत्ता पर ही नहीं, बल्कि भारत की विदेश नीति और भविष्य की राजनीतिक संरचना पर भी पड़ सकता है।

दावे के बाद से ही टीवी डिबेट्स में यह सवाल घूम रहा है—क्या चव्हाण किसी अंदरूनी जानकारी के आधार पर बोल रहे हैं? क्या वाकई एपस्टीन फाइल्स में ऐसा कुछ है, जो भारत की सत्ता को हिला सकता है? और सबसे बड़ा प्रश्न—यदि चव्हाण की बात सच साबित होती है, तो वह "मराठी नेता" कौन है, जिसका नाम चव्हाण ने इशारों में लिया?

महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त कई बड़े चेहरे सक्रिय हैं—कुछ दिल्ली की सत्ता के करीब, तो कुछ विपक्ष में अपनी भूमिका मजबूत कर रहे हैं। लेकिन चव्हाण के इस बयान ने ऐसी उत्सुकता पैदा कर दी है कि अब लोग हर संकेत, हर बयान और हर हलचल को एक नए नजरिये से देखने लगे हैं। जो भी हो, यह साफ़ है कि आने वाले हफ्ते भारतीय राजनीति के लिए बेहद रोमांचक, अनिश्चित और बहसों से भरे होने वाले हैं। एपस्टीन फाइल्स का खुलासा होगा या नहीं, उसमें क्या होगा, कौन प्रभावित होगा—यह सब अभी रहस्य है।

बलूचिस्तान में आतंक का भीषण फैलाव: महिला आत्मघाती हमले से शुरू हुई घुसपैठ, 24 घंटे में 23 से ज्यादा धमाके

(जीएनएस)। क्वेटा। बलूचिस्तान में आतंकवाद की लहर एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुँच गई है। रविवार देर रात चगाई ज़िले के नोक कुंडी इलाके में फ्रंटियर कॉर्प्स (एफसी) मुख्यालय दक्षिण पर बड़े पैमाने पर समन्वित हमला हुआ, जिसने पूरे सुरक्षा ढांचे को हिला कर रख दिया। हमले की शुरुआत उस वक्त हुई, जब बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (बीएलएफ) से जुड़ी एक महिला आत्मघाती हमलावर ने मुख्य प्रवेश द्वार पर खुद को विस्फोट से उड़ा दिया। जैसे ही विशाल धमाके ने सुरक्षा घेरा तोड़ा, उसके साथ आए अन्य हमलावर फैले धुएँ और अफरा-तफरी में परिसर में घुस गए। एफसी ने दावा किया है कि जवाबी कार्रवाई में कम से कम तीन घुसपैठियों को मार गिराया गया है। हालांकि, बीएलएफ अपने प्रचार चैनलों पर उल्टा दावा कर रहा है कि उसने एफसी को भारी नुकसान पहुँचाया है और क्षेत्र में लड़ाई अब भी जारी है। एफसी प्रवक्ता ने यह भी संकेत दिया कि हमले की योजना प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि परिसर की तलाशी के दौरान कई संदिग्ध सुराग मिले हैं। बलूचिस्तान की स्थिति सिर्फ एक हमले तक सीमित नहीं रही। उसी रात पंजगुर के गुरमाकन इलाके में एक सुरक्षा चौकी पर मुठभेड़ कई घंटों तक चली, जबकि शनिवार को क्वेटा और डेरा मुराद जमाली में सात धमाकों ने हालात और गंभीर कर दिए। इन धमाकों में रेलवे ट्रैक तक उड़ा दिया गया, जिससे कई लाइनों पर यात्रियों की आवाजाही बंद हो

गई। बलूचिस्तान पोस्ट के अनुसार, बीते 24 घंटों में कलात, केच, पंजगुर, चगाई और क्वेटा सहित कई जिलों में 23 से ज्यादा हमले हुए हैं। सेना, पुलिस और सरकारी ढाँचों के साथ-साथ रेलवे संपत्तियों को भी निशाना बनाया गया। कई इलाकों में हथियारबंद लोगों ने नाकेबंदी कर स्थानीय लोगों में दहशत फैला दी है। हमले के बाद बीएलएफ ने महिला आत्मघाती हमलावर जुंद नादरी जरीना रफ़ीक उर्फ 'तरंग माहू' की तस्वीर जारी करते हुए दावा किया कि यह पूरी कार्रवाई रेकोडिक और सिंदक प्रोजेक्ट्स से जुड़े विदेशी विशेषज्ञों और कर्मचारियों के केंद्रीय परिसर को निशाना बनाकर की गई। इन वैश्विक खनन परियोजनाओं पर पहले भी कई आतंकी हमले हो चुके हैं, और ताज़ा विस्फोटों ने सुरक्षा एजेंसियों को फिर से हाई अलर्ट पर ला दिया है।

उधर, चगाई के मुख्य सैन्य शिविर पर भी आत्मघाती हमला होने की पुष्टि हुई है, जबकि कई क्षेत्रों में सेना और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। पंजगुर के हमले की जिम्मेदारी अभी किसी समूह ने नहीं ली है, लेकिन घटनाओं की तीव्रता से साफ है कि बलूचिस्तान फिलहाल एक संगठित आतंकी अभियान की चपेट में है। पेशावर में पिछले सप्ताह हुए आत्मघाती विस्फोट के बाद से सुरक्षा बलों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, और मौजूदा हमलों ने आशंका बढ़ा दी है कि आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

चलनी चाहिए संसद, चर्चा से ही होगा समाधान

संसद के शीतकालीन सत्र के पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में विपक्ष की ओर से जो कुछ कहा गया, उससे यही साफ हुआ कि इस सत्र में अन्य अनेक मुद्दों के साथ मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर का मुद्दा जोर-शोर से उठेगा। विपक्ष को संसद में किसी भी मुद्दे को उठाने का अधिकार है, लेकिन आखिर विपक्षी दल एसआइआर को लेकर सरकार से ऐसा क्या जानना चाहते हैं, जो उन्हें नहीं ज्ञात?

यह भी ध्यान रहे कि यह सरकार की ओर से संचालित प्रक्रिया नहीं है। इसे तो चुनाव आयोग अपने संवैधानिक अधिकार के तहत करा रहा है और इसलिए करा रहा है, क्योंकि बीते लगभग दो दशक में इसे नहीं किया गया। इसके कारण मतदाता सूचियों में उन तमाम लोगों के नाम दर्ज हैं, जो या तो मर गए अथवा अन्यत्र चले गए। इसके अलावा कई नामों का दोहराव है।

मतदाता सूचियां तभी ठीक हो सकती हैं, जब एसआइआर कराया जाए, लेकिन विपक्षी दलों को इस पर ही आपत्ति है। यह कोई बात नहीं हुई कि मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने की मांग भी की जाए और एसआइआर पर आपत्ति भी उठाई जाए। विपक्ष इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकता कि बिहार में एसआइआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई के दौरान उनके वकीलों की ओर से इस संवैधानिक प्रक्रिया के विरोध में जो भी दलीलें दी गईं, वे ठहर नहीं सकीं। इसी कारण बिहार में एसआइआर की प्रक्रिया संभव हो सकी।

हालांकि विपक्ष 12 राज्यों में जारी एसआइआर का भी विरोध कर रहा है, लेकिन इसके कहीं कोई संकेत नहीं कि वह उसे रुकवा सकेगा। संसद के इस सत्र में विपक्ष एसआइआर पर जैसे चाहे वैसे सवाल उठा सकता है, लेकिन ऐसा करते हुए उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे संसदीय कार्यवाही बाधित हो। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अब कोई मुद्दा उठाने अथवा सवाल पूछने के नाम पर ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी जाती हैं जिससे सदन की कार्यवाही चलाना मुश्किल हो जाता है।

विपक्षी दलों के नेता भले ही अपनी बात की सुनवाई न होने की शिकायत करते हों, लेकिन सच यह है कि वे चाहते ही नहीं कि उनकी ओर से उठाए गए किसी मुद्दे पर सदन में कोई गंभीर चर्चा हो सके। चूंकि अब संसद का प्रत्येक सत्र हंगामे के लिए जाना जाता है, इसलिए संसद को चलाने के कुछ नए तौर-तरीके अपनाने होंगे।

उचित यह होगा कि संसद की कार्यवाही चलाने के लिए कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में जो कुछ तय होता है, उसका विवरण भी सार्वजनिक किया जाए। ऐसे किसी उपाय की आवश्यकता इसलिए है, क्योंकि कार्य मंत्रणा समिति में बनी सहमति सदन के पटल पर कहीं नजर नहीं आती। यदि संसद चलाने के नए तौर-तरीके नहीं खोजे गए तो उसका चलना मुश्किल ही होगा।

हुमायूं कबीर, अरशद मदनी और महमूद मदनी के बयान आखिर कैसे भारत का माहौल खराब कर रहे हैं?

> लिहाजा, ऐसे बयानों पर हमारे सही राजनेताओं का खामोश रहना, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा त्वरित एक्शन नहीं लेना, और सक्षम न्यायिक अधिकारियों द्वारा ऐसे मसलों पर स्वतः संज्ञान नहीं लेना इस आशंका को बल देता है कि इन नए नए जिन्ना को नया नया पाकिस्तान आज नहीं तो कल देना ही होगा।

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सहिष्णु मुल्क है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पक्षधर देश है, लेकिन इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि राजनेताओं की दंगाई प्रवृत्ति को शह दिया जाए। गुलाम भारत में, आजाद भारत में जो राजनीतिक नौटंकी दिखाई दे रही है, इस जनद्रोही प्रवृत्ति पर अविलंब अंकुश लगना चाहिए। कहना न होगा कि जिस तरह से 'मुस्लिम नेता व धर्मगुरु' यथा- हुमायूं कबीर, अरशद मदनी और महमूद मदनी के सार्वजनिक बयान भारत का माहौल खराब कर रहे हैं, वह बेहद चिंता की बात है। ऐसा इसलिए कि पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना की तरह ही ये लोग विवादित और उत्तेजक बयान दे रहे हैं जो सामाजिक और राजनीतिक तनाव बढ़ाने वाले हैं।

लिहाजा, ऐसे बयानों पर हमारे सही राजनेताओं का खामोश रहना, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा त्वरित एक्शन नहीं लेना, और सक्षम न्यायिक अधिकारियों द्वारा ऐसे मसलों पर स्वतः संज्ञान नहीं लेना इस आशंका को बल देता है कि इन नए नए जिन्ना को नया नया पाकिस्तान आज नहीं तो कल देना ही होगा। भविष्य में ऐसा नहीं हो, इसके माकूल प्रबंधन किये जाने चाहिए।

साथ ही, अफगानिस्तान से म्यामांर तक शांतिपूर्ण स्थिति हर हाल में बनाए रखने की कूटनीति व सियासत को तवज्जो देनी चाहिए और इस दिशा से भटकते नेताओं की नकेल कसना प्रशासनिक व न्यायिक अधिकारियों की प्रथम दृष्टि होनी चाहिए। साथ सैन्य अधिकारियों को आसेतु हिमालय में उधम मचाने वाले लोगों को सैंतने की खुली छूट मिलनी चाहिए। इस मामले में अमेरिकी या चीनी हस्तक्षेप बिल्कुल अस्वीकार्य होना चाहिए।

अब पहले हुमायूं कबीर के बयान पर गौर फरमाते हैं। इन्होंने बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर धमकी भरे बयान दिये हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मस्जिद बनानी होगी और इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो शहीद भी होंगे। उनके ऐसे उकसावे वाले बयान से सामाजिक तनाव और सांप्रदायिक दंगल की आशंका बढ़ रही है, जिससे माहौल बिगड़ रहा है। उनकी बयानबाजी को राजनीतिक स्वार्थ साधने वाली और समाज में फूट डालने वाली माना जा रहा है।

ऐसे में भारत के बहुसंख्यक लोगों की इच्छा है कि कबीर जैसे लोगों को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि किसी भी विदेशी आक्रांता के नाम पर भारत में अब कोई नया निर्माण नहीं होगा और पुराने निर्माणों को भी चरणबद्ध ढंग से हटाया जाएगा या फिर नामान्तरित किया जाएगा।

अब मौलाना अरशद मदनी के बयान पर नजर डालते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत-पाक रिश्तों और कश्मीर मामले पर सावधानी से विवादित बयान दिये हैं। उन्होंने भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत की पॉलिसी की आलोचना की और पाकिस्तानी आर्थिक स्थिति पर चिंता जताई, जो कई लोगों को विरोधाभासी और देशविरोधी लगा। इसके अलावा, उन्होंने भारत में मुसलमानों के प्रति भेदभाव और निशाने पर लिए जाने की बात कही, जिससे विवादित माहौल बन गया है।

ऐसे में भारत के बहुसंख्यक लोगों की इच्छा है कि अब अरशद मदनी जैसे लोगों को यह समझा देना चाहिए कि पाकिस्तान व पूर्वी पाकिस्तान यानी बंगलादेश बतौर हिस्सा दिया जा चुका है। यह हिंदुओं का हिंदुस्तान है जहां पाकिस्तान व बंगलादेश से हमदर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अब महमूद मदनी के बयान की चर्चा करते हैं। उन्होंने वंदे मातरम, जिहाद, और सुप्रीम कोर्ट पर कट्टरपंथी और विवादित टिप्पणियां की हैं। उन्होंने जिहाद को न्यायसंगत लड़ाई बताई और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर सवाल उठाए। उनके इन बयानों पर राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई है, जिसमें कहा गया है कि ऐसे बयान देश के विरोधी हैं और माहौल खराब कर रहे हैं। विहिप समेत कई संगठनों ने उनके बयानों की निंदा की है।

ऐसे में भारत के बहुसंख्यक लोगों की इच्छा है कि महमूद मदनी जैसे लोगों को भी यह समझा देना चाहिए कि मौजूदा प्रशासन ब्रिटिश प्रशासन नहीं है और भारत का प्रशासन शांतिप्रियता को बढ़ावा देता है। लिहाजा किसी भी तरह की आक्रामक प्रवृत्ति को कुचल दिया जाएगा।

यहां सर्वाधिक गौर करने वाली बात यह है कि यदि भारत का प्रशासन इन अराजक तत्वों शीघ्र नहीं निबटेगा तो ऐसे उग्र लोग देर सबेर भारत के नरम प्रशासन का खात्मा करके ही रहेंगे। ये भारत की स्थिति भी पाकिस्तान-बंगलादेश की तरह कर देंगे। आज जैसे अरब अशांत है, उसी तरह से कल हिंदुस्तान को भी अशांत बना देंगे। इसलिए इनकी शिक्षा व खान-पान को हिंसक बनने से रोकना बदलते वक्त की पहली जरूरत है।

सच कहूं तो ये बयान धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संवेदनाओं को भड़काने वाले हैं और भारत के सामाजिक समरसता को हिला सकते हैं। यह माहौल खराब करना समझा जा रहा है क्योंकि ऐसे बयान उकसावे और विवाद पैदा करते हैं। राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता के लिए ऐसे बयान अप्रामाणिक और खतरनाक माने जा रहे हैं। इसलिए समय रहते ही नए नए जिन्नों की प्रवृत्ति को कुंद करना होगा। इसके लिए हमारी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को कठोर कदम उठाने होंगे। साथ ही धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित करने के लिए यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया को बढ़ावा देकर समाजिक समरसता को बढ़ावा दिया जाए। और इस राह में बाधक लोगों को अरब मुल्कों की तरफ भेज दिया जाए।

ऐसा इसलिए कि उनके इन बयानों का सामाजिक तनाव पर काफी नकारात्मक असर हुआ है। महमूद मदनी ने मुसलमानों के खिलाफ कथित अत्याचारों का जिक्र करते हुए कहा कि जब जुल्म होगा, तब जिहाद होगा, जो एक उग्र और संवेदनशील माहौल बनाने वाला बयान है। ऐसा बयान समाज में धार्मिक पक्षपात और अलगाव को और बढ़ाता है, जिससे तनाव की विभीषिका और बढ़ जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम समुदाय को सामाजिक, कानूनी और आर्थिक रूप से कमजोर किया जा रहा है, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय में असुरक्षा और बेचैनी बढ़ रही है।

आपको याद होगा कि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जैसे वरिष्ठ नेताओं ने भी भारत में धार्मिक विभाजन और असुरक्षा के बढ़ते माहौल की चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ऐसे विभाजन और भेदभाव असहिष्णुता को उत्पन्न करते हैं, जो सामाजिक अशांति और असुरक्षा को बढ़ावा देते हैं। वास्तव में, भारत में धार्मिक नेताओं के विवादित बयानों ने जाति और धर्म के आधार पर साम्प्रदायिक तनाव और सामाजिक विभाजन को मजबूत किया है। ये बयानों सामाजिक सहिष्णुता और भाईचारे को हिला कर धार्मिक कट्टरता, नफरत और हिंसक घटनाओं को बढ़ावा देते हैं। इससे समाज में भय, अविश्वास और अलगाव की भावना फैलती है, जो सार्वजनिक शांति के लिए खतरा बन जाती है।

तल्ख अनुभव बताता है कि इस तरह के बयान साम्प्रदायिक विवादों को हवा देते हैं, जिससे समुदायों के बीच झड़पें, भड़काऊ पोस्टर, प्रदर्शन और दंगों की घटनाएं बढ़ जाती हैं। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में हाल के वर्षों में कई सांप्रदायिक तनाव और हिंसात्मक घटनाएं इसी माहौल से उपजी हैं। यह माहौल भ्रष्ट राजनीतिक फायदा उठाने वाले गुटों के लिए भी उपयुक्त होता है, जिससे सामाजिक स्थिरता में कमी आती है।

देखा जाए तो हुमायूं कबीर, अरशद मदनी और महमूद मदनी के विवादित बयानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न होने के कई कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण यह है कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संविधान द्वारा सुरक्षा प्राप्त है, जिससे बयानों को कानूनी रूप से प्रतिबंधित करना जटिल हो जाता है जब तक कि वे स्पष्ट रूप से अपराध की श्रेणी में न आएं। भारतीय दंड संहिता की धारा 295 (ए) और 153-ए के तहत ऐसे कार्य जो धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं या धार्मिक वर्गों के बीच शत्रुता बढ़ाते हैं, अवैध हैं, लेकिन इन धाराओं को लागू करने में न्यायिक विवेक और साक्ष्यों की मजबूती आवश्यक होती है।

आम तौर पर विवादित बयान अक्सर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आ जाते हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई के लिए यह साबित करना जरूरी होता है कि वे सीधे सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं या हिंसा के लिए उकसाते हैं। इसके अलावा, न्यायालयों में यह भी देखा जाता है कि धार्मिक नेताओं के बयानों को धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का भी सम्मान होना चाहिए, जिससे कार्रवाई को सीमित या सतर्कता से किया जाता है।

यही वजह है कि धार्मिक नेताओं के बयान राजनीतिक और सामाजिक संवेदनशीलता के कारण कानूनी क्रिया-कलापों का सामना कम करते हैं और बातचीत या राजनीतिक माध्यमों से हल निकालने की कोशिश की जाती है। वहीं, कुछ मामलों में राजनीतिक और सामाजिक कारणों से भी सरकार या प्रशासन कानूनी कार्रवाई में हिचकिचाते हैं क्योंकि ऐसी कार्रवाई सामाजिक विद्रूपता या बड़े सांप्रदायिक तनाव को जन्म दे सकती है। इसलिए विवादित बयानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में देरी या अड़चनें आती हैं।

बावजूद इसके, हुमायूं कबीर, अरशद मदनी और महमूद मदनी के विवादित बयानों पर राजनीतिक दलों की तीखी प्रतिक्रियाएँ आई हैं। हुमायूं कबीर के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले बयान के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति गरमा गई है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के इस विधायक के बयान पर विपक्षी दलों ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने इसे सामाजिक और धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला बताया है और कहा कि यह पुराने विवादों को फिर से उभारने की कोशिश है।

प्रेरणा

आधुनिक जीवन की सबसे मीठी और सबसे कड़वी कहानी

दुनिया में कुछ आविष्कार ऐसे होते हैं जिनका असर इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर इतना गहरा पड़ता है कि लोग भूल जाते हैं यह कब शुरू हुआ और कैसे धीरे-धीरे हमारे जीवन में समा गया। प्लास्टिक भी ऐसा ही एक चमत्कार है—एक ऐसी चीज़, जिसने सुविधा का दरवाज़ा तो खोला, लेकिन उसी सुविधा की आड़ में ऐसे खतरे भी पैदा किए जिनकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। आज यह स्थिति है कि अगर अचानक किसी सुबह प्लास्टिक दुनिया से गायब हो जाए, तो आधुनिक जीवन सिर्फ रुक ही नहीं जाएगा, बल्कि आधा संसार ठहरकर सोच में पड़ जाएगा कि अब शेष जीवन कैसे चलेगा।

एक समय था जब मिट्टी के घड़े पानी ठंडा रखते थे, लकड़ी के बक्से सामान बचाए रखते थे, कपड़े की थैली हर घर की पहचान थी और धातु के बर्तन मजबूती का दूसरा नाम थे। लेकिन जैसे-जैसे दुनिया तेज़ हुई, जीवन की रफ्तार बढ़ी, शहरीकरण फैलता गया और सुविधाओं की भूख बढ़ती चली गई—प्लास्टिक ने इंसान को जो दिया, उसे उसने खुले दिल से स्वीकार लिया। हल्का, सस्ता, टिकाऊ, रंगों-आकारों की अनंत दुनिया और किसी भी रूप में ढल जाने की चमत्कारी क्षमता—प्लास्टिक ने वस्तुओं की प्रकृति ही बदल दी।

आज घर में कदम रखते ही जो पहला दृश्य मिलता है, वह प्लास्टिक की किसी न किसी वस्तु का होता है। रसोई की बोतलें, बच्चों के स्कूल बैग, फ्रिज की ट्रे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बॉडी कवर, टिफ़िन बॉक्स, स्टोरेज कंटेनर, खिलौने, कंघे, ब्रश—हर चीज़ में प्लास्टिक का साम्राज्य फैला हुआ है। बाज़ारों में अब धातु के बजाय प्लास्टिक के रंग-बिरंगे उत्पाद ज्यादा आकर्षण खींचते हैं। उपभोक्ता के मन में यह विश्वास बिठा दिया गया है कि जो हल्का है, सुंदर है, चमकीला है और सस्ता है—वह ही आधुनिक है।

लेकिन इतने वर्षों की आदत ने इस सुविधा के पीछे छिपा खतरा धीरे-धीरे उजागर कर दिया है। वैज्ञानिकों की चेतावनियाँ अब सिर्फ किताबों में नहीं रहीं, बल्कि रोज़मर्रा की जिंदगी के हिस्से में बदलने लगी हैं। बताया जाता है कि खेतों की मिट्टी, सब्जियों और फलों में माइक्रोप्लास्टिक मौजूद है। समुद्र इतने प्लास्टिक से भर चुके हैं कि मछलियों के पेट में मिलने वाले प्लास्टिक कण अब सामान्य बात बन गई है। डर इस बात का है कि यही कण हमारे शरीर में भी पहुँचकर खून और कोशिकाओं को प्रभावित कर रहे हैं। यह दुनिया का ऐसा खाद्य चक्र बन चुका है जिसमें इंसान खुद अपनी बनाई हुई प्लास्टिक खा रहा है, पी रहा है और सांसों के साथ निगल रहा है। विडंबना यह है कि प्लास्टिक सिर्फ हमारे भोजन में ही नहीं, हमारी सोच, व्यवहार और रिश्तों में भी अपनी छाप छोड़ चुका है। संबंधों की मजबूती अब उतनी नहीं रही, जितनी लचीलापन बढ़ गया है—जैसे प्लास्टिक कभी-कभी हर आकार में ढल जाता है, वैसे ही आधुनिक जीवन के रिश्ते भी अवसरों और परिस्थितियों के अनुसार ढलते-बदलते रहते हैं। इंसान आज जितना तेज़ चलता है, उतना ही कुछ कमजोर भी होता जा रहा है।

कहने को सिंगल–यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगभग हर देश में लागू किया जा चुका है, लेकिन बाज़ार की रफ्तारें रोकना आसान नहीं। सुविधा की भूख और तात्कालिक जरूरतों ने मनुष्य को इतना व्यस्त कर दिया है कि वह खुद अपनी आदतों के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। हर साल बैठकों में प्रतिबंधों पर नए प्रस्ताव बनते हैं, नए दिशा-निर्देश जारी होते हैं, लेकिन कूड़े के ढेर में सबसे ज्यादा जो दिखाई देता है, वह प्लास्टिक ही होता है। नए जमाने की पीढ़ी तो इस बदलाव के साथ पैदा हुई है—उन्हें पैक्ड फूड और रेडी-टू-इट ड्रिंक्स में सुविधा दिखती है। वे माइक्रोवेव-सेफ कंटेनरों में खाना गर्म करते हैं, प्लास्टिक की बोतलों में पानी पीते हैं और सड़कों पर मिलने वाली पैकेजिंग को सामान्य मानते हैं। उन्हें मिट्टी की खुशबू वाली थैली या पीतल के डिब्बे पुराने जमाने की चीजें लगती हैं। आधुनिकता की भाषा बदल चुकी है, और इस भाषा के अक्षर प्लास्टिक से बने हुए हैं।

फिर भी प्रश्न यही है कि यह सुविधा कब तक चलेगी? क्या मनुष्य एक दिन जागकर यह तय कर पाएगा कि जिस चीज़ को उसने अपना सबसे बड़ा मित्र बना लिया है, वही उसकी धरती, उसके जल और उसके शरीर के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन चुका है?

शायद आने वाला समय ही इसका उत्तर देगा। लेकिन एक बात निश्चित है—प्लास्टिक ने इंसान को जितना दिया है, उतना किसी और आधुनिक आविष्कार ने नहीं दिया। और जितना लिया है, उसका अंदाज़ा दुनिया अभी लगाना शुरू ही कर रही है।

सहज कर्म-पथ का आह्वान है भगवद्गीता, अस्तित्व का अर्थ और मूल्य ही गीता का प्रतिपाद्य है

कालजयी श्रीमद्भगवद्गीता उस महाभारत का अंश है, जिसे भारतीय चिंतन परंपरा में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। महाभारत की महागाथा में धर्म की अवधारणा ही प्रमुख है। गीता का आरंभ भी धर्म शब्द के साथ होता है। धर्म का तत्व देश, काल और पात्र के सापेक्ष होता है और गतिशील जीवन-पद्धति को इंगित करता है। ईश्वर का अवतार धर्म को पहचानने और स्थापित करने के लिए होता है। धर्म को रीति और नीति से भिन्न समझना होगा। अपने से दुर्बल की सहायता करना ही परम धर्म है। इस दृष्टि से सामाजिक संदर्भ के सापेक्ष ही धर्म की समझ भी आकार लेती है। ऋग्वेद, उपनिषद और धर्मशास्त्र आदि सब का संज्ञान लेते हुए महाभारत रचा गया। भगवद्गीता महाभारत का हृदय सरीखा है।

भगवद्गीता महाभारत के भीष्म पर्व में है, पर उसके पहले वन पर्व में व्याध-गीता का भी एक आख्यान आता है। आश्चर्य यह कि दोनों हिंसा की पृष्ठभूमि में हैं। एक कसाई के घर में तो दूसरा युद्धभूमि में। भौतिक (प्रकृति) और मानसिक चैतन्य (पुरुष) का भेद दोनों में ही दिखता है। प्रकृति का सत्य विविधताओं से भरा हुआ है। मनुष्य की कल्पनाशीलता उसे चर अचर अन्य सभी जीवों या पदार्थों से अलग करती है। मनुष्य से यह अपेक्षा है कि वह पाशविक वृत्ति से ऊपर उठ कर ऊर्ध्वमुखी हो। यही जीवन में व्याप्त हीनता और क्षुधा को दूर करने वाला है। गीता की विचारधारा सदियों से देश-विदेश में मानवीय चिंतन को प्रभावित करती आ रही है। अब तक विश्व की विभिन्न भाषाओं में गीता के तीन हजार से अधिक अनुवाद हो चुके हैं। कहा जाता है कि तमाम शास्त्रों को विस्तार में पढ़ने की जगह गीता को हृदयंगम करना ही पर्याप्त है। इसमें कृष्ण स्रोत हैं और संजय सूचना या संदेश के प्रस्तोता हैं। शायद धृतराष्ट्र और अर्जुन दोनों श्रीकृष्ण के वचनों को सुनते हैं, परंतु अपने-अपने ढंग से और कदाचित भिन्न भिन्न रूपों में। अर्जुन श्रीकृष्ण से प्रश्न पूछते हैं। धृतराष्ट्र चुप रहते हैं। वे डरे सहमे हुए हैं। वे शायद मन ही मन कृष्ण के वचनों को सुनकर गुनते-आंकते हैं।

गीता में श्रीकृष्ण विश्लेषण (सांख्य) और संश्लेषण (योग) दोनों पद्धतियों का उपयोग करते हैं। उन्होंने व्यावहारिक कर्म-योग, भावनात्मक भक्ति-योग और बौद्धिक ज्ञान-योग का प्रतिपादन किया है। गीता के पांचवें अध्याय में श्रीकृष्ण शरीर को नौ द्वारों वाली एक पुरी बताते हैं। गीता द्वारा मानस का विस्तार और यथार्थ का बोध संभव होता है। कर्म का सिद्धांत यह बताता है कि आप वर्तमान परिस्थिति को तो नहीं नियंत्रित कर सकते, किंतु उस परिस्थिति के प्रति प्रतिक्रिया कैसे करें, यह जरूर चुन सकते हैं। गीता का कर्मवाद यह भी स्पष्ट करता है कि मनुष्य अपनी परिस्थितियों का स्वयं निर्माता भी है। इसका संदेश यही है कि आप स्वयं अपने जीवन के लिए उत्तरदायी हैं। हमारे बस में मात्र यही है कि हम परिस्थिति के प्रति किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं। इसीलिए गीता में श्रीकृष्ण अर्जुन को कर्म पर ध्यान देने को कहते हैं न कि फल पर।

कर्म का परिणाम भी पांच पहलुओं पर निर्भर करता है–शरीर, मन, उपकरण, विधि तथा दैव (भाग्य)। मूर्ख ही खुद को अकेले कारण मानता है। यदि हम खुद को कर्मों के परिणामों से नहीं बांधते तो कर्म भी हमको नहीं बांधते। सुख, शक्ति और स्वर्ग की कामना से किया गया कर्म जब किया जाता है तो आंख फल पर टिकी होती है न कि कर्म पर। कर्म, विकर्म और अकर्म के बीच के अंतर को समझना कठिन है। बुद्धिमान लोग कर्म फल से बिना जुड़े निर्लिप्त होकर काम करते हैं। कर्तृत्व के अभिमान से मुक्त होने और फलेच्छा का त्याग करने पर कर्म अकर्म हो जाता है। कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त होकर कर्म करना श्रेष्ठ कर्मयोगी बनाता है। सक्रिय होना कर्म है, पर परिणाम को बिना नियंत्रित करने की चेष्टा के कर्म करना कर्म-योग है। बिना किसी प्रत्याशा के कर्म के विचार को देखकर यह प्रश्न उठता है कि उस स्थिति में कर्म के लिए क्या प्रेरणा का तत्व होगा। वृक्ष और पशु अपने लिए खाद्य और सुरक्षा पाने के लिए सक्रिय होते हैं। एक मनुष्य ही है जो दूसरों के खाद्य और सुरक्षा के लिए कर्म कर सकता है। इसी दृष्टि को अपनाना धर्म है।

हमारा शरीर मरणधर्मा है और सुरक्षा चाहता है। वह सीमाएं भी बनाता है, किंतु इस शरीर में अमर आत्मा का वास है। उसे किसी किस्म की सुरक्षा या बंधन की दरकार नहीं है। अमरता और पुनर्जन्म के विचार के साथ श्रीकृष्ण मानवीय जीवन के विमर्श का पूरा नक्शा ही बदल देते हैं। शरीर का अंत अंत नहीं होता और न शरीर का आरंभ आरंभ होता है। वस्तुतः हम एक महा आख्यान का हिस्सा होते हैं। पुनर्जन्म यह बताता है कि यह विश्व हमारे पहले भी था और हमारे बाद भी रहेगा।

गीता व्यक्ति के मानसिक-आध्यात्मिक उन्नयन पर बल देती है। अस्तित्व का अर्थ और मूल्य ही गीता का प्रतिपाद्य है। कर्म मार्ग का प्रवर्तन ही उसका प्रमुख उद्देश्य है। कर्म की गति गहन होती है। कर्म से मुक्ति संभव नहीं है। कर्म की गुणवत्ता उसे करने में नहीं, बल्कि उसके पीछे निहित इच्छा के त्याग में है। त्याग इच्छाओं का अभाव है। गीता इच्छाओं से आसक्ति दूर करना चाहती है न कि कर्म से। लोक-संग्रह के लिए जीवन का ढर्रा बदलना होगा। बंधुत्व का भाव आवश्यक है। अपने स्वभाव के अनुसार कर्म में निरत होकर मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है।

अभियान

प्रयागराज का माघ मेला: आस्था, व्यवस्था और सांस्कृतिक चेतना का अंतहीन विस्तार

प्रयागराज की धरती हर वर्ष माघ महीने में उस दिव्य ऊर्जा से भर जाती है, जिसे शब्दों में बाँधना कठिन है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर बसने वाला माघ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति की उस अनंत परंपरा का जीवंत प्रतीक है, जिसमें आस्था, तप, दर्शन, जनजीवन और सामाजिक समन्वय एक ही पथ में समाहित हो जाते हैं। इस बार के माघ मेले ने अपने विशाल आकार, नई व्यवस्थाओं और पिछले महाकुंभ के प्रभाव के कारण तैयारियों को पहले ही चरण में असाधारण बना दिया है। सामान्यतः दीपावली के बाद शुरू होने वाली तैयारियाँ इस बार वर्षा थमते ही आरंभ हो गई थीं, और नवरात्रि से पूरे शहर में मानो एक नए उत्सव की हलचल फैल गई।

आगामी माघ मेला पौष पूर्णिमा 3 जनवरी से आरंभ होगा और इस अवधि में प्रयागराज की धरती करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के स्पंदन से भरी रहने वाली है। इस बार प्रमुख स्नान पर्वों पर रिकॉर्ड भीड़ पहुँचने का अनुमान है। मकर संक्रांति 14 जनवरी को लगभग तीन करोड़ लोग संगम में डुबकी लगाने आएँगे, वहीं 18 जनवरी की मौनी अमावस्या पर यह संख्या पाँच करोड़ तक जा सकती है। इसके बाद वसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर भी भीड़ की उसी अनवरत धारा के बहने की संभावना है। इसी प्रवाह को देखते हुए माघ मेला लगभग 15 फ़रवरी के आसपास पूर्ण होगा, लेकिन उसके जाने के बाद भी प्रयागराज की मिट्टी पर करोड़ों कदमों की छाप लंबे समय तक बनी रहेगी।

वर्ष 2025 में हुए महाकुंभ का अनुभव इतना विशाल था कि उसके बाद से प्रशासन की दृष्टि बदल गई है। अनुमान था कि महाकुंभ में 50 से 64 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। यह अद्भुत आकड़ा दुनिया के किसी भी आयोजन की तुलना में असाधारण था। महाकुंभ ने विश्वभर में प्रयागराज और भारतीय सांस्कृतिक आयोजन की प्रतिष्ठा को जिस ऊँचाई पर पहुँचाया था, उसी प्रभाव के कारण इस बार का माघ मेला भी सामान्य से कहीं अधिक विशाल होने जा रहा है। विदेशी आगंतुकों की संख्या आमतौर पर माघ मेले में कम रहती है, लेकिन इस बार महाकुंभ की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा के बाद अधिक संख्या में विदेशियों के आने का अनुमान है। इस दृष्टि से मेला प्रशासन की चुनौतियाँ भी बढ़ी हैं, क्योंकि पिछले वर्षों की तुलना में ढाई से तीन गुना अधिक तैयारी अपेक्षित है।

मेला क्षेत्र का निर्धारण इस पूरे आयोजन की रीढ़ है। गंगा और यमुना के जलस्तर, उनके उतार–चढ़ाव, तटों की स्थिरता, सुरक्षा, साधु–संतों की पारंपरिक दिनचर्या और उनकी अखाड़ा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लेआउट दो बार बदला गया है। संगम घाट, अरैल घाट और राम घाट को पहले से अधिक विस्तृत रूप दिया गया है, ताकि लाखों कल्पवासियों और करोड़ों स्नानार्थियों को अधिक सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित स्थान मिल सके। कल्पवासी इस मेले की आत्मा कहे जाते हैं, क्योंकि पूरे माघ महीने तक वे कुटिया बनाकर संगम के निकट तपस्वी जीवन जीते हैं। इस बार प्रशासन ने पारंपरिक कुटिया निर्माण की अनुमति नहीं दी है, लेकिन उसके स्थान पर अधिक मजबूत, सुरक्षित और अग्निरोधक टेंट स्थापित किए हैं। स्वच्छ पानी की अबाध आपूर्ति रो-रो जल वाहनों के माध्यम से की जा रही है। बायो-टॉयलेटों की संख्या कई गुना बढ़ाई गई है और पूरे क्षेत्र में सौर लाइटें तथा छोटे चार्जिंग स्टेशन लगाए गए हैं, ताकि ऊर्जा व्यवस्था भी टिकाऊ और आधुनिक दिखे।

भीड़ नियंत्रण इस मेले का सबसे संवेदनशील पहलू है। इसलिए संगम क्षेत्र में बहुस्तरीय बैरिकेडिंग, अलग-अलग मार्गों पर वन-वे मूवमेंट, ड्रोन निगरानी, मोबाइल सुरक्षा दलों की तैनाती और आने-जाने के मार्गों पर विस्तृत ट्रैफिक सिस्टम तैयार किया गया है। इस बार केवल एक स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल रूम नहीं, बल्कि शहर की सीमा में प्रवेश करने वाले हर महत्वपूर्ण क्षेत्र पर अलग-अलग शाखाएँ भी स्थापित की जाएँगी। स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा पहले की तुलना में दोगुना कर दिया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ाकर रात-दिन स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध रखने की तैयारी हो चुकी है। संगम नोज़ पर 24 घंटे एम्बुलेंस उपलब्ध रहेगी। जल-जनित रोगों पर त्वरित निगरानी के लिए विशेष टीमें, एसडीआरएफ, जल पुलिस, गोताखोर दल और बचाव नौकाएँ हर पल तत्पर रहेंगी।

स्वच्छता इस माघ मेले की विशेष पहचान बनने वाली है। पूरे क्षेत्र में 24 घंटे सफाई दल तैनात होंगे। कचरा उठाने वाले वाहन GPS से नियंत्रित होंगे। घाटों पर बायोडिग्रेडेबल कूड़ादान लगाए जाएँगे और पूरे मेला क्षेत्र को प्लास्टिक-मुक्त बनाने का अभियान निरंतर चलेगा। साधु-संतों के अखाड़ों के लिए पहले से डेढ़ गुना अधिक स्थान निर्धारित किया गया है और डिजिटल तकनीक को मेले की एक नई पहचान बनाकर पेश किया जा रहा है। सीसीटीवी आधारित भीड़ विश्लेषण, क्यूआर कोड पहचान व्यवस्था, माघ मेला मोबाइल एप, ई-रिक्शा और ऑनलाइन शटल सेवाएँ मेले को आधुनिकता से जोड़ने वाला सेतु बनेंगी।

माघ मेला अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गरिमा के लिए भी विश्वविख्यात है। रोज़ाना चलने वाली भजन संध्याएँ, वेद–पाठ, कथा प्रवचन, योग शिविर, वैदिक अनुष्ठान और मन को शांति से भर देने वाली गंगा आरती इस बार और अधिक भव्य रूप में प्रस्तुत की जाएँगी। इन कार्यक्रमों की सुंदरता, उनकी विशालता और उनका आध्यात्मिक प्रभाव स्नानार्थियों और पर्यटकों को पहले से कहीं अधिक आकर्षित करेगा।

यह माघ मेला केवल आयोजन भर नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का उत्सव है। यह वह क्षण है जब परंपरा और आधुनिकता एक ही मार्ग पर साथ चलती दिखाई देती हैं—जहाँ साधु-संतों की कुटियों से उठती धूप की सुगंध के बीच डिजिटल निगरानी की रोशनी चमकती है, जहाँ श्रद्धा की लहरों के साथ व्यवस्था की सटीकता बहती है, और जहाँ करोड़ों लोग एक ही भाव से डुबकी लगाकर अपने भीतर की पवित्रता को जगाने का संकल्प लेते हैं। यही कारण है कि इस बार का माघ मेला अब तक हुआ सबसे भव्य, सबसे विस्तृत और सबसे व्यवस्थित आयोजन बनने जा रहा है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004 (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002 and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में पारसी धर्मगुरुओं का सम्मान समारोह आयोजित हुआ

-: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- राष्ट्र निर्माण में पारसियों का महामूल्यवान योगदान रहा है
- मैडम भीकाजी कामा, होमी भाभा, टाटा, वाडिया, गोदरेज परिवारों, फील्ड मार्शल माणेक शॉ आदि पारसियों का बड़ा योगदान रहा है
- दानवीरता का दूसरा नाम पारसी हैं, पारसियों ने भगवद् गीता का 'स्वधर्म' का संदेश आत्मसात किया है

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में सोमवार को अहमदाबाद में पारसी धर्मगुरुओं का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के करकमलों से पारसी धर्मगुरुओं को सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सभी को गीता जयंती की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अपने धर्म में निष्ठापूर्वक जीना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। पारसी समाज के पूर्वजों ने भारत में आकर गीता के 'स्वधर्म' के संदेश को जिया और कभी अपने धर्म को नहीं छोड़ा है। पारसियों ने भगवद् गीता का स्वधर्म का संदेश आत्मसात किया है। अपने धर्म की रक्षा के लिए 1300 वर्ष पहले वे ईरान से स्थानांतरण कर गुजरात आए और दूध मे चीनी की तरह घुल गए। राष्ट्र निर्माण में पारसियों का महामूल्यवान योगदान रहा है।

श्री पटेल ने कहा कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता के ज्ञान को सदियों से जतन करके रखा गया है, उसी तरह पवित्र आतश की रक्षा से धर्म का अस्तित्व बनाए रखने की गाथा का युगों तक जतन करने के लिए नवसारी में टाइम कैप्सूल रखकर इतिहास को अमर रखने का कार्य पारसी समुदाय द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र को यह टाइम कैप्सूल चरितार्थ करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' की जो विभावना दी है, उसे पारसी समुदाय ने साकार किया है। साथ ही; उन्होंने पारसी समाज के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में शुरू की गई पीएम जियो पारसी योजना का भी उल्लेख किया।

पारसी समाज गुजरात के सामाजिक जीवन में समरसता से घुल गया होने का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जहाँ-जहाँ यह समुदाय बसा, वहाँ दानवीरता-परोपकारिता का बीजारोपण हुआ है। उनके पूर्वजों ने हमेशा समाज को कुछ न कुछ दिया है। इसीलिए कहा जाता है कि दानवीरता-परोपकारिता का दूसरा नाम पारसी हैं। अरीज खंभाता बेनेवोलेंट ट्रस्ट (एकेबेटी) पारसी समाज की दानवीरता की उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री ने जोड़ा कि यह ट्रस्ट हेल्थकेयर, एजुकेशन तथा समाज कल्याण सहित विभिन्न क्षेत्रों में वंचित समुदाय के उत्थान के लिए समर्पित रहा है। एचआईवी पीड़ित लोगों के लिए भी यह ट्रस्ट कल्याण के अनेक कार्य करता है। ट्रस्ट के माध्यम से हर वर्ष हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है।

श्री भूपेंद्र पटेल ने इस अवसर पर कहा कि अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी पारसी समुदाय ने अपने संस्कारों, मूल्यों तथा सूझ-बूझ को पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम काल से लेकर आज तक देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपना देने वाले मैडम भीकाजी कामा, होमी भाभा, टाटा, वाडिया, गोदरेज परिवारों, फील्ड मार्शल सैम माणेक शॉ, फरदुनजी मर्जबान, नानी पालखीवाला, सोली सोराबजी, फली नरीमान सहित पारसी अग्रणियों को इस अवसर पर याद किया।

पारसी समुदाय के प्रमुख धार्मिक अग्रणी दस्तूरजी श्री खुर्शीद दस्तूर ने अरीज खंभाता बेनेवोलेंट ट्रस्ट के कामकाज की प्रसंसा करते हुए शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने पारसी सहित सभी समाजों को साथ लेकर सबके विकास के लिए निरंतर प्रयारसत रहने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। अरीज खंभाता बेनेवोलेंट ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी श्री पीरूज खंभाता ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'विकास विद विरासत' का मंत्र दिया है। पारसी प्रिस्ट्स का सम्मान इस मंत्र को साकार करता है। विकास में अग्रसर रहने वाला गुजरात मुख्यमत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवनशैली सहित हर मामले में निरंतर प्रगति कर रहा है। उन्होंने जोड़ा कि विकसित भारत के निर्माण में पारसी समाज अपना सक्रिय योगदान देने को तत्पर है।

उन्होंने इस अवसर पर ट्रस्ट के कामकाज की जानकारी देकर आगामी समय में पारसी समाज में धार्मिक शिक्षा में आगे बढ़ रहे युवाओं के लिए शुरू की जाने वाली छात्रवृत्ति की घोषणा की। यहाँ उल्लेखनीय है कि दो दिवसीय कार्यक्रम अंतर्गत पारसी समाज की नई पीढ़ी को उनकी परंपरा तथा संस्कृति के प्रति जागृत करने वाले विभिन्न कार्यक्रमों तथा नाटक, म्यूजिक एवं कॉमेजी जैसे कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में देशभर से पारसी समाज के लोग उपस्थित रहने वाले हैं।

इस अवसर पर प्रमुख दस्तूरजी श्री टेमटन मिर्जा, प्रमुख दस्तूरजी श्री साइरस दस्तूरजी, एकेबेटी की ट्रस्टी श्रीमती परसीस अरीज खंभाता, श्रीमती बिनाइसा पीरूज खंभाता, पारसी समाज के अग्रणी, सामाजिक संस्थाओं के अग्रणी और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

सरल और तेज़ हुई कोयला-लिग्नाइट अन्वेषण की मंजूरी प्रक्रिया, सरकारी समिति से अब मंजूरी की जरूरत नहीं

(जीएनएस)। नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में कोयला और लिग्नाइट ब्लॉकों के अन्वेषण कार्यों को तेज और सरल बनाने के लिए नई प्रक्रिया लागू कर दी है। अब 2022 में गठित सरकारी समिति से अनुमोदन लेने की बाध्यता समाप्त हो गई है, जिससे भूवैज्ञानिक रिपोर्ट (जीआर) और अन्वेषण कार्यक्रमों को जल्दी और कुशलता से आगे बढ़ाया जा सकेगा। कोयला मंत्रालय के अनुसार इस कदम का उद्देश्य न केवल प्रक्रियाओं को पारदर्शी और तेज बनाना है, बल्कि निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देकर देश की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत करना है।

नई प्रक्रिया के तहत अब क्यूसीआई-एनएबीईटी से मान्यता प्राप्त और अन्य अधिसूचित समकक्ष एजेंसियों (एपीए) द्वारा तैयार कोयला एवं लिग्नाइट ब्लॉकों के अन्वेषण कार्यक्रम और भूवैज्ञानिक रिपोर्ट सीधे मंत्रालय के अनुमोदन तंत्र में भेजी जा सकती हैं। इससे अनुमोदन में आने वाली अनावश्यक देरी समाप्त होगी और पहले की तुलना में कम से कम तीन महीने की समय बचत होगी। मंत्रालय का मानना है कि इससे ब्लॉक का जल्द चालू होना संभव होगा और आवंटित कंपनियों को समय पर अपने लक्ष्य पूरे करने में मदद मिलेगी।

कोयला मंत्रालय ने बताया कि देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह कदम अत्यंत आवश्यक है। तेज, कुशल और तकनीकी रूप से सक्षम अन्वेषण से कोयला और लिग्नाइट संसाधनों का दीर्घकालिक और सतत उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। मंत्रालय ने कहा कि यह सुधार न केवल ऊर्जा क्षेत्र में दक्षता लाएगा, बल्कि यह निजी निवेशकों के लिए भी आकर्षक और भरोसेमंद माहौल तैयार करेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से अन्वेषण क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, जिससे भूवैज्ञानिक और कोयला ब्लॉक के आवंटन की प्रक्रिया में समय और संसाधनों की बचत होगी। नई कार्यप्रणाली की वजह से निवेशक अब बिना सरकारी बाधाओं के तेजी से परियोजनाओं को आगे बढ़ा सकेंगे। यह पहल देश की ऊर्जा तैयारियों को सुदृढ़ करने और कोयला तथा लिग्नाइट संसाधनों के अधिक टिकाऊ और प्रभावी उपयोग में अहम भूमिका निभाएगी। कुल मिलाकर, इस नई प्रक्रिया से कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण की मंजूरी का समय घटेगा, संसाधनों का बेहतर प्रबंधन होगा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। यह सुधार उद्योग और सरकार के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ देश में ऊर्जा परियोजनाओं को तेज़ गति से क्रियान्वित करने में मददगार साबित होगा।

नवंबर में जीएसटी संग्रह 1.70 लाख करोड़ रुपये, घरेलू राजस्व में कमी के चलते वृद्धि सीमित

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश में नवंबर माह का सकल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह इस बार मामूली बढ़त के साथ 1.70 लाख करोड़ रुपये पर रहा। यह आंकड़ा पिछले वर्ष नवंबर के 1.69 लाख करोड़ रुपये की तुलना में केवल 0.7 प्रतिशत अधिक है। विशेषज्ञों का कहना है कि संग्रह में इस सीमित वृद्धि का मुख्य कारण घरेलू राजस्व में आई गिरावट और 375 वस्तुओं पर की गई जीएसटी दर कटौती है।

जीएसटी महानिदेशालय के अनुसार, नवंबर 2025 में कुल सकल संग्रह 1,70,276 करोड़ रुपये रहा, जबकि नेट जीएसटी राजस्व 1.52 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ गया, जो 1.3 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्शाता है। अक्टूबर में जीएसटी संग्रह में 4.6 प्रतिशत की उल्लेखनीय तेजी देखी गई थी, जब कुल राजस्व 1.96 लाख करोड़ रुपये दर्ज हुआ था। इस बार घरेलू खपत में नरमी और दरों में कमी के कारण यह वृद्धि अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाई।

संग्रह का विस्तृत विवरण देखें तो सीजीएसटी के तहत 34,843 करोड़ रुपये, एसजीएसटी में 42,522 करोड़ रुपये और आईजीएसटी में 92,910 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। नेट संग्रह में सीजीएसटी 32,664 करोड़, एसजीएसटी 39,805 करोड़ और आईजीएसटी 79,611 करोड़ रुपये रहा। घरेलू राजस्व में गिरावट 2.3 प्रतिशत दर्ज की गई, जो कुल 1.24 लाख करोड़ रुपये से अधिक पर आया। इस गिरावट के पीछे मुख्य रूप से जीएसटी दरों में कटौती और घरेलू मांग में कमी का असर बताया गया है।

वहीं, आयात से होने वाला जीएसटी राजस्व इस दौरान 10.2 प्रतिशत बढ़कर 45,976 करोड़ रुपये पहुंच गया। नई दरें 22 सितंबर से लागू की गई हैं, जिसका असर नवंबर संग्रह में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हालांकि, कुल रिफंड में गिरावट आई है। नवंबर में कुल रिफंड 4 प्रतिशत घटकर 18,196 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 18,954 करोड़ रुपये था।

विश्लेषकों का कहना है कि नवंबर में जीएसटी संग्रह स्थिर तो रहा, लेकिन घरेलू खपत की नरमी और नई दरों के लागू होने के कारण तेज वृद्धि दर्ज नहीं की जा सकी। इस स्थिति से यह संकेत मिलता है कि आर्थिक गतिविधियों में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी उपभोक्ता खर्च और बाजार मांग पूरी तरह से मजबूत नहीं है। कुल मिलाकर, नवंबर का जीएसटी आंकड़ा इस बात की ओर इशारा करता है कि देश का कर ढांचा स्थिर है और आयात पर आधारित राजस्व में मजबूती देखने को मिल रही है, लेकिन घरेलू खपत में नरमी और दरों में कटौती के कारण वृद्धि अपेक्षाकृत सीमित रही। सरकार को अब घरेलू मांग को बढ़ावा देने और जीएसटी संग्रह में सतत वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

नवंबर माह में ऑपरेशन अमानत के तहत RPF द्वारा यात्रियों के 12 लाख रुपये से अधिक की कीमत के छूटे सामान को लौटाया गया

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल का रेलवे सुरक्षा बल यात्रियों को सुरक्षित, संरक्षित और आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहा है। सार्वजनिक सुरक्षा, सामाजिक कल्याण और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखते हुए, वडोदरा मंडल के रेलवे सुरक्षा बल ने विभिन्न अभियानों के तहत नवम्बर ,2025 में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है।

मंडल के रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने "ऑपरेशन अमानत" के तहत, यात्रियों के 12 लाख रुपये से अधिक की कीमत के यात्रिओं के कुल 83 छूटे हुए सामान को सफलतापूर्वक ढूंढकर उन्हें लौटा दिया।

वडोदरा मंडल के रेलवे सुरक्षा बल के रेलकर्मिओं द्वारा "आपरेशन दूसरा" के तहत बिना इजाज़त के फेरी लगाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उनके खिलाफ़ बल के जवानों द्वारा रेगुलर ड्राइव जारी है। नवंबर महीने में चलाये गए इस अभियान में कुल 1184 बिना इजाज़त फेरी लगाने वालों को गिरफ्तार किया गया और रेल अधिनियम 1989 की धारा के तहत उनका सामान ज़ब्त किया गया। इसके अलावा, उन पर एक्सेस फ़ेयर टिकट (EFT) लगाकर पेनल्टी लगाई गई। उनसे एक्सेस फ़ेयर टिकट (EFT) राशि के तौर पर कुल 1,19,440 रुपये इकट्ठा किए गए।

रेलवे सुरक्षा बल के इन सतत प्रयासों ने न केवल रेलवे परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है, बल्कि यात्रियों में रेलवे के प्रति विश्वास और सुरक्षा की भावना को भी सशक्त बनाया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में मंगलवार को गांधीनगर में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 187वीं बैठक आयोजित होगी

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी बैठक में सहभागी होंगे

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 187वीं बैठक 2 दिसंबर मंगलवार को सुबह 10.15 बजे गांधीनगर में स्वर्णिम संकुल-1 स्थित नर्मदा हॉल में आयोजित होगी।

केन्द्र तथा राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को बैंकों द्वारा दी जाने वाली ऋण सहायता तथा फ्लैगशिप कार्यक्रमों में बैंकों के परफॉर्मेंस की समीक्षा एवं सुझावों के लिए समय-समय पर यह बैठक आयोजित की जाती है।

मंगलवार को आयोजित होने वाली एसएलबीसी की इस बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार दास, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की कार्यपालक निदेशक श्रीमती सोनाली सेनगुप्ता तथा विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के वरिष्ठ प्रबंधक एवं अधिकारी सहभागी होंगे।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 की द्वितीय तिमाही में श्रेष्ठतम प्रदर्शन करने वाले 3 अग्रणी जिला प्रबंधकों का मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से ट्रॉफी तथा प्रमाणपत्र से सम्मान किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त; एसएलबीसी द्वारा जुलाई-सितंबर-2025 तिमाही में विभिन्न योजनागत क्षेत्रों में बैंकों में हुए कामकाज की ऑडियो-विजुअल प्रस्तुति तथा सर्वग्राही समीक्षा भी की जाएगी।

4 दिसंबर की अहमदाबाद-तिरुचिरापल्ली स्पेशल परिवर्तित मार्ग से चलेगी

(जीएनएस)। दक्षिण रेलवे के चेन्नई एग्मोर (MS) स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य के दूसरे चरण के तहत प्लेटफॉर्म संख्या 7, 8 एवं 9 पर किए जा रहे कार्यों के कारण लाइन ब्लॉक/पावर ब्लॉक लिया गया है, जिसके कारण अहमदाबाद-तिरुचिरापल्ली स्पेशल ट्रेन परिवर्तित मार्ग से चलेगी। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः- 4 दिसंबर 2025 की ट्रेन संख्या 09419 अहमदाबाद-तिरुचिरापल्ली स्पेशल परिवर्तित मार्ग वाया रेनिगुंटा-अरक्कोणम नॉर्थ कैबिन-मेलपक्कम-काटपाडी-वेलूर केंट-विल्लुपुरम के रास्ते चलेगी। इस दौरान यह ट्रेन अरक्कोणम, पेरम्बूर, चेन्नई एग्मोर, ताम्बरम और चेंगलपट्टू स्टेशनों पर नहीं जाएगी। मार्ग परिवर्तन के दौरान इस ट्रेन को तिरुत्तणि स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव दिया गया है। ट्रेनों के ठहराव, मार्ग और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

घुटास की डाकिया रागिनी : जंगलों में बेगा जनजाति के लिए डिजिटल भरोसे की मिसाल

(जीएनएस)। मंडला। मध्यप्रदेश के घने जंगलों और स्वच्छ हवा से भरे मंडला जिले के आदिवासी बाहुल्य गांव घुटास में हर सुबह एक नई उम्मीद कदमों की आहट के रूप में चलती दिखाई देती है। ये कदम हैं शाखा डाकपाल रागिनी राजपूत के, जो केवल पत्रों की वाहक नहीं, बल्कि डिजिटल युग में बदलाव की असली मिसाल बन चुकी हैं। खासकर बेगा जनजाति के परिवारों के लिए रागिनी वह नाम हैं, जिन्होंने सरकारी तंत्र और गांव के लोगों के बीच की दूरियों को मिटाकर विकास का एक नया रास्ता दिखाया है।

पहले घुटास में डाकघर का मतलब सिर्फ पत्रों की आवाजाही था, लेकिन अब रागिनी ने इसे डिजिटल सेवाओं का केंद्र बना दिया है। उनके कंधे पर केवल डाक बैग नहीं बल्कि डिजिटल शिक्षा, बैंकिंग सुविधा, सरकारी योजनाओं की जानकारी और लोगों के अधिकारों का भरोसा भी सहेजा जाता है। जब वह सुबह-सुबह पगडंडियों से गुजरती हैं, तो बेगा परिवारों के छोटे बच्चे उत्सुकता से रास्ते के किनारे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि रागिनी का आना किसी सूचना, योजना या राहत के आने जैसा ही माना जाता है।

डिजिटल समय में रागिनी ने सबसे बड़ा बदलाव यह किया है कि घुटास जैसे दूरस्थ गांव में भी अब लोग मोबाइल बैंकिंग, आधार-आधारित भुगतान, ऑनलाइन पेंशन और अन्य डिजिटल सेवाओं को समझने लगे हैं। पहले जहां बुजुर्गों को पेंशन के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, वहीं अब रागिनी AEPS सुविधा के माध्यम से उनके अंगूठे के एक स्पर्श पर पेंशन घर पर ही पहुंचा देती हैं। रागिनी न केवल सरकारी योजनाओं के फॉर्म भरवाती हैं, बल्कि लोगों को डिजिटल माध्यम से स्टेटस चेक करना भी सिखाती हैं। 'सुकन्या समृद्धि योजना', डाक बीमा, PMJJBY, PMSBY, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और रिकरिंग डिपॉजिट जैसी योजनाओं के लाभ पहुंचाने में रागिनी का योगदान अनमोल है। उनके आने से पहले यहां सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता बेहद कम थी, लेकिन अब हर घर में लोग यह समझने लगे हैं कि योजनाएं उनके द्वार पर ही उपलब्ध हैं। डिजिटल बदलाव का असर तेजी से घुटास में दिख रहा है। पहले जहां लोग ऑनलाइन दस्तावेज या बैंक अपडेट के लिए शहर जाते थे, अब वही कार्य रागिनी की मदद से गांव में ही पूरे हो जाते हैं। कई बेगा परिवारों ने पहली बार बचत खाते खुलवाए हैं, बच्चे ऑनलाइन छात्रवृत्ति फॉर्म भर पा रहे हैं और बुजुर्ग अपनी पेंशन स्थिति मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रागिनी के लिए यह गांव केवल सेवा का क्षेत्र नहीं, बल्कि एक परिवार है। वह हर बुजुर्ग का हाल पूछती हैं, हर बेटी के सपनों को संवारती हैं और हर घर की आवश्यकताओं को समझते हुए समाधान खोजती हैं। यही कारण है कि घुटास में उनका नाम भरोसा, सेवा और डिजिटल बदलाव का प्रतीक बन गया है।

रागिनी ने साबित कर दिया है कि एक डाकपाल सिर्फ पत्र नहीं पहुंचाता। वह समाज तक विकास, तकनीक और अवसर भी पहुंचाता है। घुटास जैसे आदिवासी क्षेत्र में डिजिटल युग की रोशनी फैलाने वाली रागिनी केवल डाकिया नहीं, बल्कि एक डिजिटल परिवर्तन की वाहक बन गई हैं, जो हर घर में उम्मीद और आत्मनिर्भरता का संदेश लेकर आती हैं।

इंदौर की 17 वर्षीय छात्रा राधिका दुबे ने पेंटिंग बनाकर खुदकुशी कर इलाके में मचाया

(जीएनएस)। इंदौर। मध्य प्रदेश के आजाद नगर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली और रहस्यमय घटना सामने आई है। 17 वर्षीय छात्रा राधिका दुबे ने अपने कमरे में फांसी लगाकर जीवन समाप्त कर लिया। इस घटना ने पूरे इलाके में शोक और हैरानी की लहर दौड़ा दी। पड़ोसियों और स्थानीय लोगों के अनुसार राधिका पढ़ाई में होनहार और शांत स्वभाव की छात्रा थी। लेकिन अब इस युवा जीवन का अंत अचानक और रहस्यमय तरीके से हो गया है। पुलिस के मुताबिक, राधिका ने मौत से पहले अपने कमरे में दो पेंटिंग बनाई थीं। पहली पेंटिंग में उसने प्रकृति का चित्र बनाया था जिसमें सूरज, पेड़ और शांत वातावरण दिखाई दे रहा था। दूसरी पेंटिंग में उसने खुद को 'बाय-बाय' करते हुए दिखाया। इस दृश्य ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद उसने अपने अंत की भावना को पेंटिंग्स के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश की थी। पेंटिंग्स के मिलने से यह स्पष्ट होता है कि छात्रा शायद किसी मानसिक या भावनात्मक संकट से गुजर रही थी, लेकिन इसका कारण अभी तक अज्ञात है। देर रात सूचना मिलने पर आजाद नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और देखा कि राधिका ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने कमरे की तलाशी ली और दोनों पेंटिंग्स को बरामद किया। फिलहाल, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि राधिका ने ऐसा कदम क्यों उठाया। स्थानीय लोग कहते हैं कि वह हमेशा खुश और मिलनसार रहती थी, इसलिए इस आत्महत्या ने सभी को झकझोर कर रख दिया। पुलिस ने राधिका का मोबाइल जब्त कर उसकी कॉल डिटेल्स, मैसेज और सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा, परिजनों और दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि आत्महत्या के पीछे की परिस्थितियों का पता लगाया जा सके। प्रारंभिक जांच में यह प्रतीत हो रहा है कि राधिका मानसिक तनाव या व्यक्तिगत समस्या का सामना कर रही थी। पुलिस मर्ग दर्ज कर मामले की गहन जांच कर रही है। छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। इस घटना से स्तब्ध हैं और उनके अनुसार यह किसी चेतावनी की तरह है कि मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। राधिका के घरवाले अभी भी सदमे में हैं और उनके पास इस दुखद घटना की कोई समझ नहीं है। पड़ोसियों और रिश्तेदारों का कहना है कि राधिका हमेशा अपने कमरे में अकेले रहती थी और शायद किसी परेशानी या तनाव के कारण उसने ऐसा कदम उठाया। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह कोई आकस्मिक घटना थी या कोई लंबे समय से चल रही समस्या का परिणाम। इस घटना ने इंदौर के आजाद नगर और आसपास के क्षेत्रों में चिंता और शोक की स्थिति पैदा कर दी है। लोगों का कहना है कि युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता की बेहद जरूरत है। राधिका की आत्महत्या ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या समाज और परिवार अपने बच्चों की मानसिक समस्याओं को समय पर पहचान और उनका समाधान कर पा रहे हैं।

दिल्ली कार बम धमाका: एनआईए की बड़े पैमाने पर छापेमारी कई डिजिटल डिवाइस जब्त-साजिश की परतें खुलने लगीं

(जीएनएस)। दिल्ली के दिल दहला देने वाले कार बम धमाके को लेकर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) तेजी से अपनी जांच आगे बढ़ा रहा है। 10 नवंबर को लाल किले के बाहर हुए इस धमाके के बाद से एजेंसी लगातार साजिश की कड़ियों को जोड़ने में लगी है। सोमवार का दिन इस दिशा में और भी अहम साबित हुआ, जब एनआईए ने जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एक साथ दबिश दी। शोपियां, कुलगाम, पुलवामा और अवंतीपोरा के शांत गांवों में अचानक सुरक्षा बलों की गाड़ियों की आवाज गूंजी और संदिग्ध ठिकानों पर घंटों तक तलाशी चली। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी एक स्थान पर छापेमारी की गई।

इन सभी जगहों पर एनआईए टीमों को ईमेल, कॉल लॉग, चैट, वीडियो और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डेटा से जुड़े कई महत्वपूर्ण डिजिटल उपकरण मिले हैं, जो जांच की दिशा को आगे बढ़ाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एजेंसी ने बताया कि इन सभी डिवाइसों की फॉरेंसिक जांच से धमाके की साजिश के डिजिटल ट्रेल सामने आने की उम्मीद है।

इससे पहले भी एजेंसी ने 26 और 27 नवंबर को हरियाणा के फरीदाबाद और अल-फलाह यूनिवर्सिटी परिसर में दो मुख्य आरोपियों—डॉ. मुजम्मिल शकील गनी और डॉ. शाहीन सईद—के ठिकानों पर बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया था। उन छापों में भारी मात्रा में नकदी, विदेशी मुद्रा, सोना और अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिली थी, जिसने जांच को नई दिशा दी। एनआईए को संदेह है कि ये लोग न सिर्फ धमाके की योजना का हिस्सा थे, बल्कि बड़े आतंकी नेटवर्क से भी जुड़े हो सकते हैं। अब तक कुल सात प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, और सभी से पूछताछ लगातार जारी है। कई संदिग्धों ने अपने नेटवर्क, पैसे के प्रवाह और पाकिस्तान सहित बाहरी तत्वों से संपर्क को लेकर महत्वपूर्ण सुराग दिए हैं। इन्हीं सुरागों के आधार पर एजेंसी लगातार नई जगहों पर छापेमारी कर रही है।

एनआईए अधिकारियों ने कहा है कि धमाके में शामिल आतंकी मॉड्यूल के हर सदस्य को ट्रैक करने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और अन्य राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों के साथ व्यापक समन्वय किया जा रहा है। कश्मीर में आतंकवाद के पुराने ठिकानों की गतिविधियों की भी बारीकी से जांच की जा रही है, क्योंकि शुरुआती इनपुट इस बात की ओर इशारा करते हैं कि साजिश का एक बड़ा हिस्सा वहीं से संचालित हो सकता है। एजेंसी ने भरोसा जताया है कि इस हमले से जुड़े सभी आरोपी जल्द ही कानून के शिकंजे में होंगे। अभी तक हुई पूछताछ में जो नए तथ्य और कड़ियाँ सामने आई हैं, उन्हें जोड़ने का काम तेजी से जारी है। एनआईए के मुताबिक कई ऐसे नाम सामने आए हैं जिनकी भूमिका संदिग्ध है और जिन तक पहुंचना इस जांच का अगला चरण होगा।

दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां दौड़ने लगीं अब 210 किलोमीटर का सफर सिर्फ ढाई घंटे में

(जीएनएस)। दिल्ली से देहरादून की पहाड़ियों तक जाने वालों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षा में खड़ी एक बड़ी खुशखबरी आखिर सामने आ गई है। वर्षों से 6–7 घंटे की थकाने वाली यात्रा और बीच-बीच में लगने वाले जाम से परेशान यात्रियों को अब राहत मिलने जा रही है। दिल्ली–सहारनपुर–देहरादून एक्सप्रेसवे पर रविवार रात से ट्रायल रन शुरू हो गया है, और इसके साथ ही गाड़ियाँ नई चमचमाती सड़क पर सरपट दौड़ने लगी हैं। यह ट्रायल रन ऐसे समय में शुरू हुआ है जब हाल ही में ट्रांसमिशन लाइन से जुड़ी गंभीर तकनीकी समस्या के कारण निर्माण कार्य में एक महीने की देरी हो गई थी। लेकिन अब बैरिकेडिंग हटते ही एक्सप्रेसवे का असली रूप जनता के सामने दिखाई देने लगा है। गीता कॉलोनी से बैरिकेडिंग हटने के बाद पहली बार जब वाहनों ने एक्सप्रेसवे पर कदम रखा, तो ऐसा लगा जैसे दिल्ली की रफ्तार को नए पंख मिल गए हों। 210 किलोमीटर की दूरी, जिसे अभी तक 5 से 6 घंटे में पूरा करना मजबूरी थी, अब सिर्फ ढाई घंटे में पूरा हो सकेगी। फिलहाल लोग देहरादून जाते समय अक्सर दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेसवे का सहारा लेते हैं, लेकिन इस नए कॉरिडोर के आने के बाद यात्रा का स्वरूप ही बदल जाएगा। 11,868.6 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से तैयार हुआ यह प्रोजेक्ट जल्द ही दिल्ली–एनसीआर के लोगों को जाम से बड़ी राहत देने वाला है। ट्रायल रन के दौरान मोटरसाइकिल, कारें और अन्य छोटे वाहन इस पर लगातार चल रहे हैं। एक मोटरसाइकिल सवार ने बताया कि एक्सप्रेसवे खुलने से सफर सिर्फ तेज नहीं होगा, बल्कि सुगम भी बनेगा। "ट्रैफिक से बचेंगे, समय बचेगा, और सफर भी बेहतर होगा," उसने बताया—यही भावना इस नए रास्ते को लेकर आम लोगों में साफ दिखाई दे रही है।

एक्सप्रेसवे अक्षरधाम से शुरू होकर बागपत, शामली और सहारनपुर जैसे पश्चिमी यूपी के महत्वपूर्ण जिलों से गुजरता हुआ देहरादून तक पहुंचता है। इसके उद्घाटन की तैयारी भी पूरे जोरों से चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि नए साल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका औपचारिक उद्घाटन कर सकते हैं। यह उद्घाटन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि लाखों यात्रियों के लिए एक नई यात्रा संस्कृति की शुरुआत बन सकता है।

इस परियोजना को समय पर पूरा करने का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा बागपत-सहारनपुर के बीच की ट्रांसमिशन लाइन थी, जो सीधे एक्सप्रेसवे के ऊपर से गुजरती थी। न इसे आसानी से हटाया जा सकता था और न ही इसे बंद किया जा सकता था, क्योंकि इससे सहारनपुर क्षेत्र की बिजली व्यवस्था ठप हो जाती। लंबे समय तक शटडाउन की योजना बनाना और सुरक्षा प्रोटोकॉल के मध्य संतुलन बनाते हुए इस लाइन को व्यवस्थित तरीके से हटाना इंजीनियरों और विद्युत विभाग के लिए बड़ी चुनौती थी।

काठमांडू में 74 करोड़ रुपये के क्रिप्टो कारोबार में दो गिरफ्तार, जांच जारी

(जीएनएस)। काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू में क्रिप्टो करेंसी के अवैध कारोबार में संलिप्त दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पुलिस ने कुल 74 करोड़ रुपये के लेनदेन का पता लगाया है। यह गिरफ्तारी पिछले एक सप्ताह में क्रिप्टो कारोबार में हुई दूसरी बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।

पुलिस अधीक्षक पवन कुमार भट्टाराई ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्तियों में 36 वर्षीय विशाल डंगोल, जो मूल रूप से मोरंग जिले के रहने वाले हैं, और 45 वर्षीय उमेश श्रेष्ठ, जो काठमांडू के कलंकी इलाके में निवास करते हैं, शामिल हैं। दोनों को विशेष सूचना के आधार पर सोमवार को बिजुलीबजार क्षेत्र से पकड़ा गया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने क्रिप्टो लेनदेन में इस्तेमाल किए गए पांच मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं।

भट्टाराई ने बताया कि यह गिरफ्तारी पिछले हफ्ते हुई दो युवकों की गिरफ्तारी के बाद की गई है, जिनके खिलाफ भी क्रिप्टो कारोबार में संलिप्तता की जांच चल रही थी। उन्होंने कहा कि मामले की गहन जांच जारी है और आगे भी ऐसे अवैध लेनदेन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के बड़े क्रिप्टो लेनदेन की जाँच कठिन है, क्योंकि डिजिटल मुद्रा का लेनदेन आसानी से ट्रैक नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद पुलिस ने आधुनिक तकनीक और डिजिटल फॉरेंसिक सहायता से मामले को तेजी से आगे बढ़ाया है। गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ जारी है, जिससे यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उनके पीछे और कौन-कौन लोग इस अवैध कारोबार में शामिल हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि नेपाल में क्रिप्टो करेंसी के कारोबार पर नियंत्रण की कमी के कारण इस तरह के बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और अवैध लेनदेन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस गिरफ्तारी से यह संदेश भी गया है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी पर कड़ी निगरानी रख रही हैं और दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में पीछे नहीं हटेंगी।

इस मामले ने काठमांडू के निवेशकों और आम जनता में भी सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाने की जरूरत को रेखांकित किया है। नेपाल सरकार और पुलिस दोनों ने जनता से अपील की है कि क्रिप्टो निवेश से जुड़े लेनदेन में सतर्क रहें और केवल वैध प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करें।

उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं का नया अध्याय: विशेषज्ञ डॉक्टरों को अब हर महीने मिलेंगे 7 लाख रुपये

(जीएनएस)। उत्तराखंड के ऊँचे पहाड़ों में फैली ठंड, दुर्गम रास्ते, सीमित संसाधन और लंबे समय से महसूस की जा रही विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी—इन सबके बीच आखिरकार राज्य सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। धामी सरकार ने तय किया है कि अब पर्वतीय जिलों के सरकारी अस्पतालों में तैनात विशेषज्ञ डॉक्टरों को सात लाख रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। यह सिर्फ वेतन वृद्धि नहीं है, बल्कि पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाओं में नई जान फूंकने की कोशिश है, जिसने पूरे राज्य में उम्मीदों की लौ जला दी है। यह फैसला 'यू कोड–वी पे' योजना में किए गए संशोधन के बाद सामने आया है। इस योजना का मूल उद्देश्य है—जहां डॉक्टर जाने से हिचकें, वहां सरकार प्रोत्साहन देकर उन्हें भेजे। जैविक कठिनाइयों के बीच जीवन बचाने का काम करने वाले डॉक्टरों को पहाड़ में काम करने के लिए पहले 5 लाख रुपये तक मिलता था, लेकिन अब जब सुपर स्पेशलिटी सेवाएँ देना अत्यावश्यक हो गया है, तो सरकार ने वेतन बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया है। इस फैसले को स्वास्थ्य विभाग के भीतर ही नहीं बल्कि आम जनता के बीच भी राहत की तरह देखा जा रहा है। वर्षों से चौखुटिया, बेलेश्वर, गैरसैंण, धुमाकोट, पिलखी, पिथौरागढ़ जैसे इलाके लगातार यह आवाज उठा रहे थे कि अगर डॉक्टर नहीं आएंगे तो पहाड़ों की स्वास्थ्य व्यवस्था कभी मजबूत नहीं हो पाएगी। पहाड़ के लोग जानते हैं कि एक मामूली बीमारी भी यहाँ गंभीर रूप ले सकती है, और गंभीर बीमारियों का इलाज तो अक्सर मैदानी शहरों पर ही निर्भर रहता था। कई बार मरीजों को देर रात सड़कों की हालत से जूझते हुए हल्द्वानी या देहरादून तक ले जाने में समय ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता था।

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने साफ कहा है कि यह सिर्फ वेतन बढ़ाने का फैसला नहीं बल्कि एक लक्ष्य है—"पहाड़ का हर मरीज, हर परिवार यह महसूस करे कि उनकी पहुँच में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा है।" उन्होंने बताया कि जहां-जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है, वहां प्राथमिकता के आधार पर तैनाती होगी।

इस बदलाव की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इससे पहाड़ का अस्पताल अब सिर्फ इमारत नहीं होगा—बल्कि एक भरोसा बनेगा। विशेषज्ञ डॉक्टरों के आने से ऑपरेशन थिएटर सक्रिय होंगे, गंभीर बीमारियों के इलाज में देरी कम होगी और मरीजों को मैदानी अस्पतालों की ओर भागना कम पड़ेगा। साथ ही मैदानी अस्पतालों पर बढ़ता दबाव भी कम होगा और पूरे राज्य की चिकित्सा व्यवस्था संतुलित होगी।

पहाड़ों को हमेशा से विकास की गति में पिछड़ा समझा जाता रहा है, लेकिन यह कदम बताता है कि अगर इरादा मजबूत हो, तो पहाड़ भी अवसरों की धरती बन सकते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि डॉक्टर इस प्रोत्साहन का कितना लाभ उठाते हैं और कितनी संख्या में विशेषज्ञ पहाड़ों का रुख करते हैं। अगर यह योजना सफल होती है, तो यह न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकती है।

पहाड़ के घरों में इस समय एक ही आशा है—डॉक्टर आएँ, और स्वास्थ्य सेवाओं की वह रोशनी लौटे जो वर्षों से इंतज़ार में थी।

चुनाव आयोग पर जानकारी लीक करने का आरोप, टीएमसी का बड़ा हमला—बीजेपी को फायदा पहुंचाने की साजिश बताई

(जीएनएस)। पश्चिम बंगाल की राजनीति में रविवार को उस समय हलचल मच गई जब तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आयोग बीजेपी नेताओं को चुनिंदा सूचनाएं लीक कर रहा है और एक "स्वायत्त संस्था" के बजाय "बीजेपी का विस्तारित अंग" बनकर काम कर रहा है। टीएमसी ने दावा किया कि पिछले एक महीने से जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान राज्य में तनाव का माहौल बना हुआ है और इसी तनाव ने कम से कम 40 लोगों की जान ले ली है। टीएमसी के अनुसार इनमें चार बीएलओ भी शामिल हैं। पार्टी ने इस स्थिति के लिए सीधे चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के हाथ "खून से सने हुए हैं" क्योंकि यह पूरा संकट आयोग की लापरवाही और "पक्षपातपूर्ण रवैये" से पैदा हुआ है।

टीएमसी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम सवाल उठाए—सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को SIR प्रक्रिया में "एक करोड़ लोगों के नाम हटाए जाने" की जानकारी पहले कैसे मिल गई? और विधानसभा चुनाव दो से तीन चरणों में कराने की उनकी भविष्यवाणी किस आधार पर थी? वरिष्ठ मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि अगर आयोग वास्तव में स्वतंत्र है, तो क्या वजह है कि बीजेपी नेताओं को चुनावी चरणों की संख्या और मतदाता सूची में संभावित परिवर्तनों की भनक पहले से लगी हुई है?

टीएमसी सांसद पार्थ भौमिक ने भी इसी आशंका को और गहरा किया। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी लगातार यह दावा कर रहे थे कि बंगाल की मतदाता सूची से एक करोड़ नाम काटे जाएंगे। यह आंकड़ा उन्हें कैसे मिला—किसने दिया—और क्यों दिया? भौमिक ने कहा कि चुनाव आयोग का दायित्व पारदर्शिता है, लेकिन वह जनता को जवाब देने के बजाय "बीजेपी की दुष्प्रचार मशीन" के लिए जानकारी लीक करने में लगा है।

टीएमसी नेताओं के अनुसार इन बयानों के चलते आम लोगों में डर का माहौल है। कई परिवारों को डर है कि बिना किसी ठोस कारण के उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे। पार्टी का कहना है कि पिछले कुछ हफ्तों से SIR प्रक्रिया के दौरान कई जगहों पर तनाव, झड़पें और दबाव देखा गया है, जो इस असुरक्षा को और बढ़ा रहा है।

कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 10 रुपये घटाए गए, घरेलू रसोई गैस की कीमत स्थिर

(जीएनएस)। नई दिल्ली। साल के आखिरी महीने के पहले दिन व्यवसायिक उपयोगकर्ताओं के लिए राहत भरी खबर आई है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस विपणन कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 10 रुपये तक की कटौती की घोषणा की है। हालांकि, घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह नई दरें सोमवार से प्रभावी हो गई हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, नई दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1590.50 रुपये से घटकर 1580.50 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है। कोलकाता में इसका मूल्य 1694 रुपये से घटकर 1684 रुपये हो गया है। मुंबई में 1542 रुपये का सिलेंडर अब 1531.50 रुपये में उपलब्ध होगा, जबकि चेन्नई में 1750 रुपये वाला सिलेंडर अब 1739.50 रुपये में मिलेगा। दूसरी ओर, घरेलू रसोई गैस के दाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नई दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 853 रुपये ही बनी हुई है। मुंबई में यह 852.50 रुपये, लखनऊ में 890.50 रुपये, करगिल में 985.50 रुपये, पुलवामा में 969 रुपये और बागेश्वर में 890.50 रुपये में उपलब्ध है।

विशेषज्ञों का मानना है कि कमर्शियल गैस की कीमत में यह मामूली कटौती व्यापारियों और छोटे व्यवसायों के लिए कुछ राहत देने वाली है। वहीं, घरेलू गैस की कीमत स्थिर रहने से आम परिवारों को इस महीने भी अप्रत्याशित खर्च का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकारी कंपनियों का यह कदम ईंधन बाजार में स्थिरता बनाए रखने और महंगाई के प्रभाव को कम करने की दिशा में एक छोटा प्रयास माना जा रहा है। इस बदलाव के साथ ही उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे अपने सिलेंडर वितरण और भुगतान संबंधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से अवश्य जांच लें, ताकि कोई भ्रम या असुविधा न हो।

एलओसी पर घुसपैठ के चार प्रयास नाकाम, आठ आतंकी ढेर: बीएसएफ ने साझा की जानकारी

(जीएनएस)। श्रीनगर। नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर घुसपैठ के प्रयासों में इस साल उल्लेखनीय कमी आई है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के कश्मीर फ्रंटियर के महानिरीक्षक (आईजी) अशोक यादव ने सोमवार को हुमहामा मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस साल अब तक एलओसी पर कुल चार घुसपैठ प्रयास हुए हैं, जिनमें से दो प्रयास ऑपरेशन 'सिंदूर' से पहले और दो इसके बाद किए गए।

इन चार घुसपैठ प्रयासों में कुल 13 आतंकवादी शामिल थे। बीएसएफ और सेना के संयुक्त अभियानों में आठ आतंकवादियों को मार गिराया गया जबकि पांच को पीछे धकेल दिया गया। आईजी अशोक यादव ने कहा कि नियंत्रण रेखा पर सेना और बीएसएफ के प्रभावी समन्वय ने घुसपैठ के प्रयासों में कमी लाने में निर्णायक भूमिका निभाई है। उनके अनुसार, उनके कार्यकाल में हुए अभियान घुसपैठ को नाकाम करने और आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों में महत्वपूर्ण रहे।

आईजी ने यह भी बताया कि अधिकांश ऑपरेशन बीएसएफ के खुफिया इनपुट पर आधारित थे। उन्होंने कहा कि खुफिया जानकारी साझा करना जारी रखा गया, जिससे आतंकवादियों के लिए सुरक्षित मार्ग को बंद करना, उनकी आपूर्ति लाइन को निष्क्रिय करना और हथियार भंडार को पुनः प्राप्त करना संभव हुआ। इस रणनीति के परिणामस्वरूप आतंकवादी गतिविधियों को रोकने और सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिली।

उन्होंने आगे कहा कि नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा व्यवस्था में तकनीकी उपकरणों, पैट्रोलिंग और सूचना नेटवर्क का बेहतर उपयोग किया गया है। इससे न केवल घुसपैठ प्रयास कम हुए बल्कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में भी सफलता मिली। बीएसएफ के अनुसार, यह संकेत है कि समन्वित रणनीति और सतत निगरानी से सीमा सुरक्षा मजबूत बनी हुई है।

आईजी अशोक यादव ने कहा कि एलओसी पर सुरक्षा बनाए रखना प्राथमिकता है और बीएसएफ लगातार नए खुफिया तंत्र और आधुनिक उपकरणों के जरिए आतंकवादियों की हर हरकत पर नजर रख रहा है। उनका मानना है कि इस तरह की सतर्कता और तैयारी से सीमा पर सुरक्षा की स्थिति और मजबूत होगी और भविष्य में घुसपैठ के प्रयासों में और कमी आएगी।

प्रयागराज में अवैध धर्मांतरण के आरोप में दो गिरफ्तार, पुलिस ने किया कार्रवाई

(जीएनएस)। प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में पुलिस ने अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने के मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। यह घटना रविवार रात की है, जब कैन्ट थाना क्षेत्र की पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपितों को हिरासत में लिया और उन्हें न्यायालय में पेश कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की।

पुलिस उपायुक्त नगर मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों में खुल्दाबाद थाना क्षेत्र के लूकरगंज निवासी सी.पी. राजे पुत्र एम.एम. पीटर और कैन्ट थाना क्षेत्र के म्योराबाद निवासी अनिल थामस पुत्र सदा शिव पिल्लै शामिल हैं। डीसीपी नगर ने बताया कि 29 नवंबर को नगर कोतवाली क्षेत्र के हीवेट रोड निवासी अमित मिश्रा ने पुलिस को तहरीर देकर सूचना दी थी कि म्योराबाद स्थित पादरी पीटर राजू के घर में अवैध धर्मांतरण का काम चल रहा है।

तहरीर में बताया गया कि आरोपी पादरी पीटर राजू और अनिल थामस लोगों को दूसरे धर्म में परिवर्तित करने के लिए पैसों का लालच दे रहे थे और नौकरी दिलाने का वादा कर धर्म परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। इस सूचना पर वादी अमित मिश्रा अपने साथी शुभम कुशवाहा, विजय पाण्डेय आदि के साथ मौके पर पहुंचे और इस कार्य का विरोध किया। विरोध करने पर आरोपितों ने वादी पक्ष के लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया और मारपीट भी की।

इस मामले की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की। जांच के दौरान रविवार रात पुलिस टीम ने दोनों आरोपितों को पकड़ लिया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि आगे भी जांच जारी रहेगी और यदि इस मामले में और कोई संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

प्रयागराज जिले में अवैध धर्मांतरण के मामलों पर प्रशासन ने कड़ी नजर रखने की बात कही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन के नाम पर लालच देकर प्रभावित करना कानूनी अपराध है और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

संभल में सहायक बीएलओ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, इलाके में मचा हड़कंप

(जीएनएस)। संभल। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के नखासा थाना क्षेत्र के चौकुनी गांव में सोमवार तड़के एक असमय और रहस्यमय मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। मृतक की पहचान 40 वर्षीय अरविंद कुमार के रूप में हुई है, जो अमरोहा की तहसील हसनपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय फैय्याज नगर में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत थे। इसके साथ ही वे बूथ संख्या 226 पर सहायक बीएलओ के रूप में भी तैनात थे।

परिवार के अनुसार, घटना वाली सुबह करीब 4 बजे अरविंद कुमार की पत्नी प्रतिभा उन्हें जगाने कमरे में गईं। कई प्रयासों के बाद भी जब अरविंद उठे नहीं, तो उन्होंने तुरंत परिजनों और गांववालों को सूचना दी। कुछ ही देर में उनकी मृत स्थिति की पुष्टि हुई, जिससे परिवार सदमे में आ गया।

अरविंद के पीछे पत्नी प्रतिभा और दो बच्चे—13 वर्षीय गरिमा और 10 वर्षीय लविश—छोड़ गए हैं। दोनों बच्चे

अमरोहा जिले के ढ़वारसी गांव स्थित वेदांत स्कूल में पढ़ते हैं। परिवार और ग्रामीण इस अचानक हुई मौत से स्तब्ध हैं और पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई है।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नखासा थाने के इंस्पेक्टर संजीव बालियान ने बताया कि फिलहाल कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन शिकायत मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के आधार पर मामले की गहन जांच की जाएगी।

गांव में सहायक बीएलओ की मौत को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ ग्रामीण इसे स्वास्थ्य संबंधी कारणों से जोड़ा जा रहे हैं, तो कुछ इसे संदिग्ध परिस्थितियों से जोड़कर देख रहे हैं। पुलिस ने हालांकि इसे संदिग्ध मानते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास के ग्रामीणों से जानकारी जुटाई जा रही है। इस घटना ने न केवल परिवार को गहरे सदमे में डाला है, बल्कि पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और प्रशासनिक सतर्कता की आवश्यकता पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। ग्रामीण प्रशासन से तत्काल कार्रवाई और स्पष्टता की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि घटना के असली कारणों का पता लगाया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के उपाय किए जा सकें।

झांसी में दिल्ली-सागर बस पलटी, क्रेन बुलानी पड़ी, यात्री बाल-बाल बचे

(जीएनएस)। झांसी। सोमवार सुबह दिल्ली से मध्य प्रदेश के सागर जा रही एक बस झांसी में पलटने की घटना में बाल-बाल बच गई। यह हादसा ग्वालियर रोड पर सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के ग्रासलैंड चौकी के पास उस समय हुआ, जब चालक ने सड़क पर जाम देख बस को पीछे मोड़ने का प्रयास किया। संतुलन बिगड़ते ही बस पलट गई और उसमें बैठे यात्री फंस गए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। बस में लगभग 30 लोग सवार थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। पलटी बस में यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोग और राहगीर तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। सूचना मिलते ही सीओ सिटी लक्ष्मीकांत गौतम और सीपरी बाजार पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर बस की खिड़कियों के शीशे तोड़कर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। सौभाग्य से कोई गंभीर चोटिल नहीं हुआ। बस में सवार तीन यात्रियों—

गौरव कुमार और उनके दो परिजन—को हल्की चोटें आईं, जिन्हें पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार देने के बाद छुट्टी दे दी गई। बस का रजिस्ट्रेशन नंबर बीआर 03 पीबी 2614 है और यह खुशबू बस सर्विस के तहत दिल्ली से सागर की यात्रा कर रही थी। पलटी हुई बस को क्रेन की मदद से सीधा किया गया और यात्रियों को आगे की यात्रा के लिए सुरक्षित रवाना किया गया। सीओ सिटी लक्ष्मीकांत गौतम ने बताया कि घटना में किसी प्रकार की गंभीर जनहानि नहीं हुई और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करके बड़े हादसे को टाल दिया और यात्री सुरक्षित बाहर निकाले गए। स्थानीय लोगों और प्रशासन की तत्परता ने इस घटना में बड़ी आपदा को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यात्री हादसे के बाद अपनी सुरक्षा और सड़क पर सतर्कता की अहमियत को लेकर जागरूक हुए हैं। प्रशासन ने भी इस मार्ग पर आने वाले वाहन चालकों को अतिरिक्त सतर्क रहने और नियमों का पालन करने की सलाह दी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।

घने कोहरे से रेलवे परिचालन प्रभावित, कई ट्रेनें अस्थायी रूप से रद्द

(जीएनएस)। बरेली। उत्तर भारत में सर्दियों के मौसम के चलते घना कोहरा ट्रेनों के संचालन को प्रभावित कर रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल ने सुरक्षा कारणों से कई महत्वपूर्ण ट्रेन सेवाओं में बदलाव किए हैं, ताकि कोहरे में यात्रा सुरक्षित बनी रहे। कोहरे के समय ट्रैक पर दृश्यता (Visibility) कम हो जाती है, जिससे ट्रेनों को धीमी गति से चलाना पड़ता है और लाइन क्षमता घट जाती है। इसी कारण कई गाड़ियां अस्थायी रूप से रद्द कर दी गई हैं या उनके फेरे कम कर दिए गए हैं।

मंडल द्वारा जारी सूची के अनुसार, लालकुंआ–आनंद विहार टर्मिनस एक्सप्रेस (15059) 2 दिसंबर 2025 से 12 फरवरी 2026 तक पूरी तरह से बंद रहेगी। इसके अलावा काठगोदाम–जम्मूतवी (12207/12208), कानपुर–काठगोदाम (12209/12210) और लालकुआं–अमृतसर (14615/14616) एक्सप्रेस भी दिसंबर से फरवरी के बीच कई तिथियों पर नहीं चलेंगी। इसी प्रकार दिल्ली–काठगोदाम, मुरादाबाद–रामनगर, हावड़ा–काठगोदाम और सिंगरौली/शक्तिनगर–टनकपुर रूट पर चलने वाली कई ट्रेन सेवाओं की आवृत्ति में भी कमी की गई है।

पूर्वोत्तर रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक संजीव शर्मा ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले रेलवे की वेबसाइट, मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन नंबर पर ट्रेन की स्थिति और समय-सारणी की जानकारी अवश्य लें। उन्होंने कहा कि कोहरे के समय ट्रेन परिचालन प्रभावित होता है, इसलिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार रेग्यूलेशन लागू किया गया है।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह सभी बदलाव यात्रियों की सुरक्षा और शीतकालीन ऑपरेशन की सुचारूता को ध्यान में रखकर किए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि दिसंबर से फरवरी के बीच उत्तर भारत में कोहरे की स्थिति सामान्य रहती है, जिसके चलते समय-समय पर ट्रेन संचालन प्रभावित हो सकता है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे कोहरे वाले मार्गों पर अपनी यात्रा में अतिरिक्त समय का इंतजाम रखें और स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी हासिल करें।

इस प्रकार, सर्दियों में घने कोहरे के चलते रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कई अहम ट्रेन सेवाओं में बदलाव किया है।